स्वदेशी पत्रिका

# अनुक्रम

वर्ष–24, अंक–5
बैशाख–ज्येष्ठ 2073, मई 2016

*संपादक*
**विक्रम उपाध्याय**

*पृष्ठ सज्जा एवं टंकन*
**सुदामा दीक्षित**

*कार्यालय*
**धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग**
**रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022**
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

**आवरण कथा** – पृष्ठ–6

## विदेशी कंपनियों के मकड़जाल में ई–कॉमर्स

स्वदेशी संवाद एवं अवनीश कुमार

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज

**11 व्यापार**
निर्यात में गिरावट, व्यापार संतुलन बिगड़ा
..... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

**15 मुद्दा**
सूखा पीड़ितों के प्रति संवेदना
..... देविंदर शर्मा

**17 अर्थव्यवस्था**
रूपए को मजबूत करने की जरूरत
..... डॉ. अश्वनी महाजन

**19 अर्थव्यवस्था**
संकेत तो सुहाने हैं
..... डॉ. सुभाष शर्मा

**21 नीति**
रोजगारपरक टैक्स प्रणाली बनें
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

**23 जल संग्रह**
पुरखों के पदचिह्नों पर काश हम भी चलते
..... पंकज चतुर्वेदी

**25 पद्धति**
22 अप्रैल कैसे बना पृथ्वी दिवस?
..... अरूण तिवारी

**27 जयंती**
युग पुरुष महाराणा प्रताप
..... डॉ. विजय वशिष्ठ

**30 आयुर्वेद**
आयुर्वेदः जल ही जीवन है
..... स्वदेशी संवाद

**33 व्हाटसएप**
लू लगने से मृत्यु क्यों?

# पाठकनामा

## सूखा राहत पर हील हवाला क्यों?

लगभग 13 राज्य और वहां रहने वाले 35 करोड़ लोग सूखे के शिकार है। लेकिन देश में अभी तक उन पर सिर्फ बहस ही हो रही है। कोई ठोस योजना या पैकेज समय पर सामने नहीं आने के कारण लोगों में हताशा तेजी से घर कर रही है और वहीं पलायन एवं आत्महत्या का दौर लगातार जारी है। संसद में इस मामले पर हुई बहस का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री चौ. वीरेंद्र सिंह ने यह आश्वासन तो दिया कि मोदी सरकार के कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और उनका ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा लेकिन उन्होंने भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की, जिससे कोई तत्काल राहत की कोई बड़ी बात सामने आएं। प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार मिल रहे है, उनसे सूखा राहत पैकेज के बारे में विचार विमर्श कर रहे है किंतु प्रधानमंत्री कार्यालय से पैकेज चलकर जब तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। यह कहा जा रहा है कि 15 जून तक मानसून आ जायेगा, क्या तब तक किसान इस लायक बचेंगे कि खेतों में बिजाई कर सके? सूखे का पूर्व आकलन होना चाहिए था और इससे निपटने के उपाय बहुत पहले होने चाहिए थे लेकिन अफसोस हमारी राजनीति, हमारी शासन पद्धति और नौकरशाही इस मामले में कम ही संवेदनशील है।

**सत्यव्रत त्रिपाठी,** *लखनऊ, उत्तर प्रदेश*

*****

## जल पर जागरूकता के लिए साधुवाद

स्वदेशी का अप्रैल अंक हाथ में है, पानी पर जिस तरह से विस्तृत जानकारी एवं तथ्यपरक रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, उससे तो यहीं अहसास होता है कि हम गहरे जल संकट में है। यदि हम जल्दी सजग ना हुए, जल स्रोतों का संरक्षण ना किया और पानी के दुरूपयोग पर अंकुश ना लगाया, तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के लिए खून बहेंगे। आवरण कथा 'भयानक जल संघर्ष' समयोचित एवं परिस्थिति अनुकूल है।

**विनोद नेगी,** *उत्तराखंड*

**आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।**


**संपादकीय कार्यालय**

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)


## उन्होंने कहा

**पानी की कमी के कारण कई क्षेत्रों में आर्थिक विकास दर 6 फीसदी तक नीचे गिर सकती है।**

जिम योंग किम
विश्व बैंक प्रमुख

**हम कई देशों को पैसे देते है लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं मिलता। परमाणु संपन्न पर अस्थिर पाकिस्तान को संभालने के लिए हम भारत की मदद ले सकते है।**

डोनाल्ड ट्रम्प
अमरीकी रिपब्लिकन उम्मीदरवार

**क्या धौनी में इतना कुछ बचा है कि अगले 4 साल वहीं भारत के कप्तान बने रहे।**

सौरव गांगुली
पूर्व कप्तान

**सोनिया गांधी की नागरिकता कौन छीन रहा है। वे तिहाड़ में रहे या १० जनपथ, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता।**

सुब्रह्मण्यम स्वामी
राज्यसभा सांसद

**ईटली में मेरे रिश्तेदार रहते है जिसका मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं भारत में ही अंतिम सांस लूंगी।**

सोनिया गांधी
अध्यक्ष, कांग्रेस

संपादकीय

# मॉरिशस रूट पर अंकुश!

मॉरिशस के जरिये भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर क्या सरकार निगाह रखेगी? काफी दिनों से उठ रही मांग के अनुसार सरकार ने यह संकेत दिया है कि 1 अप्रैल 2017 से मॉरिशस रूट के जरिये निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों पर अल्पकालीन पूंजी अभिवृद्धि कर लगायेगी। हालांकि 2017 से 2019 तक यह कर की दर भारतीयों पर लागू 15 फीसदी की दर से आधी होगी, फिर भी एक ऐसा प्रयास तो हुआ है जिससे काले धन को मॉरिशस के जरिये भारत में लाने वालों पर थोड़ा अंकुश लगेगा। मालूम हो कि भारत और मॉरिशस के बीच यह करार है कि वहां के जरिये भारत में निवेश करने वाली कंपनियों पर किसी भी प्रकार का कोई कर भारत में नहीं लगाया जायेगा। इसे हम डबल टैक्स एवायडेंस कन्वेंशन (डीटीएसी) भी कहते है। दोनों देशों के बीच डीटीएसी पर 1983 में हस्ताक्षर हुए थे और लगभग 33 साल बाद इस कन्वेंशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव हम करने जा रहे है। कुछ लोग अभी से ही यह शोर मचाने लगे है कि यदि मॉरिशस रूट के जरिये आने वाले निवेश पर कोई कर लगाया जाता है तो न सिर्फ विदेशी निवेश प्रभावित होगा बल्कि यहां निवेशित पूंजी भी बाहर जा सकती है। इस तरह के विचार वाले लोग संभवतः मॉरिशस रूट के जरिये होने वाले काले कारोबार को या तो जानते नहीं, या फिर जानबूझकर इसका समर्थन कर रहे है। वैसे तो मॉरिशस रूट को लेकर कई सनसनीखेज रिपोर्टें आ चुकी हैं लेकिन ताजा जानकारी अगस्ता वेस्टालैंड हेलिकॉप्टर डील में कथित रिश्वतखोरी के मामले में आई है। ईडी को शक है कि अगस्ता रिश्वत का पैसा मॉरिशस रूट से एफडीआई के रूप में भारत आया। ये पैसे चॉपर डील के रिश्वत में भारतीय अधिकारियों और नेताओं को मिले। ईडी यह पता लगाने में लगा है कि आखिर ये पैसे किस कंपनी के खाते में गए और उनका भारतीय नेताओं या अधिकारियों से क्या संबंध है। अभी ये शुरुआती जानकारी हैं। लेकिन किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि मॉरिशस रूट से आये रिश्वत के पैसे आसानी से ट्रेस कर लिए जाएंगे। इस मॉरिशस रूट में इतने पेंच हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। दुनिया के किसी भी आदमी या कपंनी को मॉरिशस में अपनी एक नई कंपनी खोलने और वहां से भारत पैसा एफआईडी के रूप में भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रूट का अभी तक गलत इस्तेमाल ही होगा। डबल टैक्स एवायडेंस कन्वेंशन यानी भारत और मॉरिशस के बीच यह करार कि मॉरिशस से आने वाले किसी भी निवेश पर भारत में कोई कर नहीं लगेगा, फायदा ज्यादातर काली कमाई को भारत में लाकर सफेद करने के लिए ही हुआ है। दूर क्यों जाएं, शीना बोरा हत्याकांड में दो प्रमुख आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके तीसरे पति पीटर मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया में भी मॉरिशस रूट के जरिये ऐसी एक कंपनी न्यू सिल्क रूट एडवायजर से एफडीआई आया था जिसके छह प्रवर्तकों में से चार पर इनसाइडर ट्रेडिंग करने का मुकदमा चला था और दो को जेल भी हुई थी। हाल ही में भारत में एविएशन का बिजनेस शुरू करने वाली एयर एशिया पर भी मॉरिशस रूट के जरिये काला धन लाने का मामला चला था। भारत के सरकारी खजाने को ही नहीं, आम आमदी को भी यह मॉरिशस रूट भारी नुकसान पहुंचा रहा है। मशहूर यूएस 64 घोटाले में भी मॉरिशस रूट का हाथ था, जहां से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर रातों रात यूएस 64 में हजारों करोड़ के कारोबार होने लगे और एकाएक पैसे बाहर भी चले गये। नतीजा हुआ कि यूएस 64 का बाजा बज गया। पैसा ले गये मॉरिशस रूट से आए सटोरिये और सरकार को यूएस 64 के लिए बेलआउट पैकेज देना पड़ा। 2जी घोटाले में भी मॉरिशस रुट की भूमिका रही। जिस स्वान टेलीकॉम का पक्ष लेने के कारण ए.राजा को जेल हुई उस स्वान टेलीकॉम का रूट भी मॉरिशस का ही था। सीबीआई का मानना है कि स्वान टेलीकॉम में स्वीटजरलैंडस का पैसा मॉरिशस में पंजीकृत कंपनी मावी इनवेस्टमेंट फंड के जरिये आया। मॉरिशस रूट को लेकर संसद में कई बार मुद्दे गंभीर रूप से उठ चुके हैं। भाजपा नेता सुब्रम्णयम स्वामी मॉरिशस रूट को तुरंत बंद करने की आवाज वर्षों से लगा रहे हैं पर अभी तक कोई भी सरकार इस पर गंभीरता से नहीं सोंच रही थी। पहली बार इस दिशा में मोदी सरकार ने एक पहल की है। हालांकि मॉरिशस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कोई कर नहीं है। इसलिए भारत में किसी को कर देने पर डबल टैक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन इससे भारत में धडल्ले से काले धन लाने के खेल पर अवश्य अंकुश लगेगा।

# विदेशी कंपनियों के मकड़जाल में ई-कॉमर्स

*अमरीका लगातार ई–कॉमर्स कंपनियों में एफडीआइ खोले जाने की वकालत कर रहा था। फिलहाल, अमेजन एवं ईबे जैसी ग्लोबल कंपनियां देश में ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कारोबार कर रही हैं। घरेलू कंपनियों में स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी फर्मे इस कारोबार में हैं।*

**– स्वदेशी संवाद एवं अवनीश कुमार**

**मोदी सरकार** ने रिटेल मार्केट प्लेस फॉर्मेट वाली ऑनलाइन रिटेल कंपनियों में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। यानि इसका फायदा अमेजन व ईबे जैसी विदेशी और फ्लिपकार्ट व स्नैपडील जैसी घरेलू कंपनियों को होगा। सरकार का तर्क है 100 फीसदी ऑटोमैटिक एफडीआई की मंजूरी केवल ऑनलाइन खुदरा बिक्री की सुविधा देने वाली कंपनियों को ही दी है, इंवेंट्री आधारित ई–कॉमर्स कंपनियों को नहीं। जो कंपनियां खुद सामान खरीदकर ऑनलाइन बिक्री करेंगी, वे इंवेंट्री आधारित मॉडल में आएंगी। सरकार का इरादा इसके माध्यम से देश में अधिक से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट प्लेस फॉर्मेट वाली ई–कॉमर्स कंपनियों से आशय ऐसी फर्मो से है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। ये फर्मे खुद ग्राहकों को उत्पाद सप्लाई नहीं करती, बल्कि ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच पुल का काम करती हैं। कहीं यह फैसला किसी के दबाव में तो नहीं हुआ। अमरीका लगातार ई–कॉमर्स कंपनियों में एफडीआइ खोले जाने की वकालत कर रहा था। फिलहाल, अमेजन व ईबे जैसी ग्लोबल कंपनियां देश में ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कारोबार कर रही हैं। घरेलू कंपनियों में स्नैपडील और फ्लिपकार्ट जैसी फर्मे इस कारोबार में हैं। अभी तक एफडीआइ को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं होने के बावजूद ये कंपनियां विदेशी निवेश ला चुकी हैं। सरकार ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मार्केट प्लेस फॉर्मेट वाली ई–कॉमर्स कंपनी कुल बिक्री का 25 फीसद से अधिक किसी एक वेंडर या उसकी सहयोगी कंपनियों के जरिये नहीं बेच सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट प्लेस आधारित ऑनलाइन रिटेल कंपनी को उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक से अधिक वेंडरों को अपने साथ जोड़ना होगा। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि ई–कॉमर्स में नौकरियों की बहार आयेगी।

मार्केट प्लेस केवल एक तकनीकी प्लेटफार्म है जो खरीददार और बेचने वाले को

खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया जा सकता है और कहां नहीं। इससे ये भी साफ हुआ है कि मार्केट प्लेस अब विक्रेता की ओर से लॉजिस्टिक सुविधाएं, पेमेंट कलेक्शन और कस्टमर केयर की सुविधाएं भी दे सकता है।

गौरतलब है कि भारत में ई–कॉमर्स के बी2सी मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमेशा से प्रतिबंधित रहा है। हालांकि यह उन ई–कामर्स कंपनियों के लिए कभी भी बाधा नहीं रहा जिन्होंने मजे से इस नियम की धज्जियां उड़ाईं और बड़ी मात्रा में विदेशी फंड उठाए। कई मौकों पर प्रवर्तन निदेशालय ने इन मामलों में जांच शुरू की पर वह जांच कहां तक पहुंची ये कभी पता नहीं चल सका। अब तक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ ही भारतीय उद्यमी भी नीतिगत खामियों का फायदा उठाते रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म की शक्ल में हजारों विक्रेताओं को उनके सामान बेचने का मंच मुहैया कराने वाली एमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट और स्नैप डील जैसी कंपनियों को अभी तक प्रौद्योगिकी सहायक माना जाता रहा है, ई–रिटेलर नहीं। क्योंकि उनका दावा है कि वे खुद के गोदामों में माल नहीं रखतीं। इसलिए एफडीआई की अनुमति नहीं होने के बाद भी वे ई–कॉमर्स के कारोबार में बनी रहीं।

**खुद अमेजन ने भी स्वीकार किया कि भारत पहला देश है जहां इतनी जल्दी वे एक बिलियन डालर की बिक्री का आंकड़ा पार कर गए हैं।**

### अमेजन का मामला

अमेजन, अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2012 में अमेजन एशिया पैसेफिक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर की सहायक कंपनी के रूप में कर्नाटक में गठित हुई। इसकी दूसरी शेयरधारक कंपनी अमेजन यूरेशिया होलडिंग्स एसएआरएल लग्जमबर्ग थी। इसने अपनी वेबसाइट 'अमेजन डॉट इन' के नाम से 2013 से व्यावसायिक गधिविधियों की शुरुआत की। एक साल के भीतर ही अमेजन भारत में एक बिलियन डालर के बिक्री के आंकड़े को पार कर गई। खुद अमेजन ने भी स्वीकार किया कि भारत पहला देश है जहां इतनी जल्दी वे एक बिलियन डालर की बिक्री का आंकड़ा पार कर गए हैं।

सितंबर 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजन पर रिटेल व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति के

## मेक इन इंडिया का मजाक बनकर रह जायेगा

**अखिल भारतीय व्यापार महासंघ** (कैट) के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खांडेलवाल का कहना है कि इस मोदी सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे मझौले या छोटे उद्योगों को कुछ फायदा हुआ हो। खांडेलवाल यह भी कहते है कि भाजपा यह भी भूल गई कि व्यापारी उसके परंपरागत वोटर है और ई–कॉमसे में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी देकर सरकार ने उन्हीं के पेट पर लात मार दी है। वे सरकार पर आरोप लगाते है कि सरकार ने इस तरह की नीतियों को लागू करने से पहले किसी भी भारतीय व्यापारी संगठन से कोई राय मशवरा नहीं किया। इस तरह की नीतियों के कारण भारतीय बाजार पर चीन की कंपनी अलीबाबा जैसी का दबदबा हो जायेगा जिनके प्लेटफार्म पर 12 लाख विक्रेता पहले से ही है। इनमें अधिकतर विक्रेता इलेक्ट्रोनिक्स समान, मोबाईल फोन और हार्डवेयर के व्यापार से जुड़े हुए है। जाहिर है अलीबाबा चीनी कंपनियों को ही ज्यादा तव्वजो देगी भारतीयों को नहीं। खांडेलवाल इस बात की आशंका जताते है कि इस नीति से देश में चीनी सामान की बाढ़ आ जायेगी और भारतीय उत्पादक और निर्माता मुहं ताकते रह जायेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी जिस मेक इन इंडिया की बात करते है वह इस तरह की नीतियों के कारण असमय फेल हो जायेगी। ❑

उल्लंघन का आरोप लगाया। यह शंका थी कि अमेजन सीधे ग्राहकों को सामान बेच रहा था और इसे अपने यहां रजिस्टर्ड वेंडर्स के मार्फत बिकता हुआ दिखा रहा था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जांच करने को कहा गया। इसी सिलसिले में व्यवसाय कर अधिकारियों ने अमेजन पर आरोप लगाया कि जब वेंडर का सामान अमेजन के पूर्ति केंद्रों पर आ जाते हैं तब उसका स्वामित्व अमेजन का हो जाता है। ऐसे में अमेजन मूल्य वर्धित कर (वैट) का भुगतान करने का उत्तरदायी है न कि सिर्फ सेवा कर, जो कि वह वर्तमान में कर रहा है। हालांकि अमेजन का तर्क था कि वह सिर्फ थर्ड पार्टी विक्रेता के सामान के स्टोर की सहूलियत देता है न कि उनका स्वामित्व रखता है। अधिकारी यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले सामानों की कीमत भी अमेजन प्रभावित करने की कोशिश करता है।

अगस्त 2014 में अमेजन और कैटामारन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेज ने संयुक्त रूप से प्रिओन बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया। यह एक प्राइवेट इनवेस्टमेंट फर्म थी जिसके प्रमोटर इन्फोसिस से संस्थापक नारायण मूर्ति थे। इसमें 51 प्रतिशत शेयर सीएमएस के थे जबकि 48 प्रतिशत शेयर अमेजन एशिया पैसिफिक रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर तथा 1 प्रतिशत शेयर अमेजन यूरेशिया होल्डिग लग्जमबर्ग के थे।

प्रिओन ने सितंबर 2014 में क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया जिसमें उसका शेयर 99.99 प्रतिशत था। बाकी बचा शेयर अर्जुन नारायणस्वामी के पास था जो प्रिओन की तरफ से ही नामित किए गए थे। यही क्लाउडटेल एक समय तक अमेजन डॉट काम पर होने वाली कुल बिक्री के 40 प्रतिशत से अधिक का हिस्सेदार था। इस तरह यह साफ है कि कैसे अमेजन ने भारत के डाउनस्ट्रीम निवेश या अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का फायदा उठाकर क्लाउडटेल को खरीदने में पैसा लगाया। बड़ी छूटों का क्या होगा

उद्योग विशेषज्ञों की राय है कि डीआईपीपी के प्रेस नोट से सस्ते दामों और बड़ी छूटों का रास्ता बंद हो जाएगा और बाजारों को अब अपने विक्रेता आधार का विस्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, इसमें थोड़ा शक है। ई–कॉमर्स साइटों द्वारा बड़ी छूटें देना संभव हुआ क्योंकि इनके पास विदेशों से सस्ता और आसान पैसा उपलब्ध हो रहा था। इससे इन साइटों ने ग्राहकों को लुभाने की सारी रणनीतियां बनाईं। हां, अब ये सब रुक सकता है लेकिन इसलिए नहीं कि डीआईपीपी ने प्रेस नोट जारी कर दिया है बल्कि इसलिए कि फंडिंग पार्टियां अब पैसा देना बंद कर रही हैं। सोचिए अगर शीर्ष दस बड़े निवेशक जिन्होंने भारत में ई–कॉमर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और भारत में ई–कॉमर्स के वैल्यूएशन को प्रेरित किया है, प्रेस नोट 3 पढ़ने के बाद एक साथ आते हैं और भारतीय ई–कॉमर्स कंपनियों में 5 अरब डालर निवेश करने का वादा करते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए बड़ी छूटें देना बंद कर देंगी? हां, इससे मार्केट प्लेस अपने विक्रेताओं का निस्संदेह विस्तार करेगा जैसा कि

## मंच ने जताई चिंता, दुकानदारों को होगी मुश्किल

**स्वदेशी जागरण मंच** ने ई–कॉमर्स में 100 फीसदी विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से आने की मंजूरी पर गहन विचार विमर्श किया। मंच ने इस विषय एवं व्यापार से जुड़े लगभग 40 प्रतिनिधियों के साथ इस विषय की गहन समीक्षा की। वक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के कदम से भारतीय दुकानदारों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। चर्चा के दौरान इस बात का भी जिक्र आया कि सरकार ने जल्दीबाजी में और बिना पूर्ण समीक्षा के ही ई–कॉमर्स में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को मंजूरी दे दी।

मंच के अखिल भारतीय सहसंयोजक डा. अश्वनी महाजन ने कहा कि देश में खुदरा व्यापार से जुड़े करोड़ों लोगों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वदेशी जागरण मंच किसी भी तरह की तकनीक का विरोध नहीं करता और ऑन लाईन बिजनेस का एक तरह से समर्थन ही करता है, लेकिन सरकार के इस कदम से विदेशी सामानों की सप्लाई ज्यादा बढ़ जायेगी और घरेलू व्यापारी हलकान होगें। उन्होंने यह भी कहा कि ई–कॉमर्स में इस निवेश नीति को लेकर कई तरह के भ्रम अभी भी है, जिन्हें समय रहते दूर किया जाना जरूरी है। ❑

वो करता आया है। वो इसलिए कि वह उपभोक्ताओं के सम्मुख और ज्यादा विकल्प पैदा कर सके और अपने व्यवसाय के जोखिम को अधिक से अधिक विक्रेताओं के बीच बांटकर कम कर सके। इसमें प्रेसनोट की कोई खास अहमियत नहीं है।

### तो अब क्या होगा

अब इसके संभावित परिणामों पर बात की जा सकती है। सबसे पहली बात ये कि वैश्विक मार्केट प्लेस जैसे अलीबाबा और राकुटेन की ताजा चाल यह होगी कि ये 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ सीधे भारत में प्रवेश करें। हालांकि स्पष्ट रूप से पहले भी कानून ने यह कभी नहीं रोका। जैसे ईबे अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से सालों से भारत में काम कर रही है जो कि पूरी तरह से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा कानूनों के अनुरूप है। अमेजन को अपने पसंदीदा इन्वेंटरी मॉडल को लाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इस प्रेसनोट से उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। एकल ब्रांड रिटेलर्स अब अपने स्टोर्स के अलावा ई–कॉमर्स साइट्स भी खोल सकेंगे जो कि उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर अनुभव होगा। चूंकि कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ है सिवाय इसके कि इसने मार्केट प्लेस को परिभाषित कर दिया है, अब संभावना यह है कि कई कंपनियों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामलों में जांच का सामना करना पड़ सकता है।

### इनका क्या होगा

लेकिन यहां कई और मामले भी हैं जिन पर विचार करना समीचीन होगा। प्रेसनोट 3 ई–कॉमर्स को वस्तुओं के साथ ही डिजिटल उत्पादों को भी डिजिटल नेटवर्क पर खरीदने और बेचने के रूप में परिभाषित करता है। सवाल यह है कि अब आईआरसीटीसी,

क्लियरट्रिप और यात्रा डॉट कॉम और ऐसे ही अन्य सेवा प्रदाता जो टिकट की बुकिंग को डिजिटल फार्म में देते हैं, ये भी मार्केट प्लेस ही हैं और वेंडरों यानी एयरलाइन कंपनियों के टिकट को डिजिटल रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। इनमें से कुछ ने तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हासिल किया है। मजे की बात यह है कि एक वेंडर या कहें कि एक एयरलाइन से ही इनकी बुकिंग 25 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो इनका भविष्य क्या होगा?

डीआईपीपी के प्रेस नोट ने ई–कामर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति को स्पष्ट तो किया है पर अब भी कई सवाल बाकी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बिजनेस 2 कन्ज्यूमर मॉडल के ई–कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है तो फिर उसमें अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश या डाउनस्ट्रीम निवेश का क्या औचित्य है? आखिर यही वो छेद है जहां से होकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑनलाइन रिटेल में घुस रहा है और अब तक जिसका फायदा अमेजन और फ्लिकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां उठाती रही हैं। प्रेस नोट 3 की शर्तों में कहा गया है कि मार्केट प्लेस मॉडल में ई–कॉमर्स प्रदाता कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वहां बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी।

**बिजनेस २ कन्ज्यूमर मॉडल के ई-कॉमर्स में एफडीआई की अनुमति नहीं है तो फिर उसमें अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश या डाउनस्ट्रीम निवेश का क्या औचित्य है? आखिर यहीं वो छेद है जहां से होकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑनलाइन रिटेल में घुस रहा है।**

अब तक अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे मार्केट प्लेस विभिन्न तरीकों से कैश बैक और वेंडरों को छूट के बदले भुगतान के जरिए दाम कम रखकर ग्राहकों को लुभाते रहते थे। दरअसल मार्केट प्लेस में कीमतों का निर्धारण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी के बल पर तो ई–कॉमर्स कंपनियां अब तक ऑफलाइन रिटेलरों ज्यादा छूट देने का दावा कर रहे थे। क्या इसे काबू कर पाना सचमुच आसान होगा?

### फ्लिपकार्ट की कहानी

फ्लिपकार्ट की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। इसका गठन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2008 में हुआ और इसने अपनी व्यावसायिक गतिविधियां अप्रैल

– जुलाई 2009 से शफ्लिपकार्ट डॉट कॉमश वेबसाइट के नाम से शुरू किया। पहले यह ऑनलाइन रिटेल वितरण व्यवसाय में थी, पर बाद में यह थोक वितरक के रूप में काम करने लगी। इसके प्रमोटरों ने 2009 में डब्ल्यू एस रिटेल नाम से एक कंपनी का गठन किया जो फ्लिपकार्ट पर विभिन्न सामानों की फुटकर बिक्री कर रही थी। 2011–12 का ऑडिट बताता है कि फ्लिपकार्ट पर डब्ल्यू एस रिटेल एकमात्र विक्रेता कंपनी काम कर रही थी। 2009 से 2012 के बीच फ्लिपकार्ट ने 180 मिलियन डालर विदेशी फंड जुटाए लेकिन जब इस पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर पड़ी तो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम के प्रमोटरों ने डब्ल्यू एस रिटेल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और अपने शेयर भी दूसरों को दे दिए। यहां पर भी अमेजन की तरह कंपनियां बनाने और नियमों के बीच से निकलने की कोशिश की गई।

साफ है कि ये सारे जुगाड़ बी2बी मॉडल के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करके और नीतिगत कमियों का फायदा उठाकर उससे रिटेल बिजनेस में फायदा कमाने के लिए किए जा रहे थे। अब औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के इस नए दिशा–निर्देश से इसपर थोड़ा लगाम लगने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि ई–कामर्स कंपनी के मार्केट प्लेस पर होने वाली कुल बिक्री में किसी भी एक कारोबारी की 25 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं हो सकती। इससे उन कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है जो जाहिर तो ये करती हैं कि वे सिर्फ मार्केट प्लेस हैं परंतु चतुराई से कंपनी ढांचे बनाकर इन्वेंटरी मॉडल पर सामान बेचती हैं। अमेजन की क्लाउडटेल और फ्लिपकार्ट की डब्ल्यूएस रिटेल इसके बड़े उदाहरण हैं जिनका इन कंपनियों की कुल बिक्री में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। ❑❑

# कालेधन पर रोक के लिए सरकार कितनी तैयार?

सरकार द्वारा भारत और विदेशों में कालेधन की समस्या पर रोक लगाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं –

- कड़े दंड वाले प्रावधानों के साथ एक नया काला धन अधिनियम लागू किया गया।
- 29 मई, 2014 को जारी अधिसूचना के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एम.बी. शाह की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया गया। विशेष जांच दल के कई सिफारिशों पर कार्यवाही की गई।
- घरेलू कालेधन के लिए एक नई आय घोषणा योजना की शुरूआत की गई।
- कठोर कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप लगभग 50,000 करोड़ रूपये के अप्रत्यक्ष कर चोरी को पकड़ा गया। इसके साथ ही 21,000 करोड़ रूपये की अघोषित आय का भी पता चला। गत दो वर्षों में तस्करी गतिविधियों में जब्त किये गये सामान की राशि बढ़कर 3963 करोड़ रूपये पहुंच गई। यह गत दो वर्षों के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक है।
- गत दो वर्षों के 1169 मामलों के मुकाबले 1466 मामलों में कानूनी कार्रवाई की शुरूआत की गई। इसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- कालाधन शोधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध से आय की परिभाषा में संशोधन किया गया जिससे देश के बाहर स्थित संपत्ति जिसे जब्त करना संभव न हो के लिए भारत में समान संपत्ति की कुर्की या अधिकरण को संभव किया जा सके।
- कालाधन शोधन अधिनियम में धारा (8) को जोड़ा गया ताकि विशेष न्यायालय के निर्देश पर कालाधन शोधन के अपराध के परिणामस्वरूप हानि उठाने वाले दावेदार को जब्त संपत्ति फिर से लौटाई जा सके।
- सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 जिसमें सीमा शुल्क से जुड़े झूठे घोषणाओं या दस्तावेजों से जुड़े अपराधों को विधेयक अपराध बनाया गया। व्यापार पर आधारित कालेधन शोधन पर रोक लगाई जा सके।
- कालाधन (अघोषित विदेश आय और संपत्ति) और अधिरोपण कर अधिनियम 2015 की धारा 51 के अंतर्गत किसी कर दंड या ब्याज से इच्छानुसार बचने के अपराध को पीएमएलए के अंतर्गत अधिसूचीबद्ध अपराध बनाया गया।
- डीएनएफबी सेक्टर में जोखिम राहत के लिए राजस्व विभाग द्वारा उठाये गये कदम निम्नलिखित हैं–
  - पीएमएलए की उपधारा 2 (1) (एसए) (6) के अंतर्गत निर्धारित व्यापार या व्यवसाय करने वाले को 15.4. 2015 को बीमा आढ़ती अधिसूचित किया गया।
  - पीएमएलए की उपधारा 2 (1) (एसए) (2) के अंतर्गत निर्धारित व्यापार या व्यवसाय करने वाले को 17.4. 2015 को पंजीयक या उपपंजीयक अधिसूचित किया गया।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 में वित्त अधिनियम 2015 के द्वारा संशोधन किये गये संशोधनों के अंतर्गत फेमा की धारा–4 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के विदेशी मुद्रा विदेशी प्रतिभूति या अचल संपत्ति अर्जित करने की स्थिति में भारत में समान राशि को जब्त करने और अधिग्रहण करने के संशोधन किया गया हैं। ❑

# निर्यात में गिरावट, व्यापार संतुलन बिगड़ा

**देश के निर्यातों** में निरंतर गिरावट के कारण विगत 16 माह से हमारे निर्यात घटते ही चले जा रहे हैं और इस गिरावट के क्रम में मार्च–2016 में भी देश के निर्यातों में 5.5 प्रतिशत की गिरावट आयी है। मार्च–2015 के निर्यातों से तुलना करने पर भी मार्च 2016 के निर्यातों में 5.47 प्रतिशत की कमी सामने आयी। निर्यातों में इस अनवरत कमी के फलस्वरूप मार्च 2016 में तो हमारे निर्यात मात्र 22.71 अरब डालर के ही रह गए हैं, जो दिसंबर 2014 से अब तक के मासिक निर्यातों में न्यूनतम है। विगत वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल–मार्च 2015–16 के निर्यात भी वर्ष 2014–15 की तुलना में घटकर 261.13 अरब डालर (17,08,841.43 करोड़ रुपये) के न्यूनतम स्तर पर आ गये हैं। जबकि अप्रैल–मार्च 2014–15 की अवधि में देश के कुल निर्यात 310.33 अरब डालर (1896348.40 करोड़ रुपये) के रहे हैं। इस प्रकार देश के निर्यातों में विगत 12 महीनों की अवधि में डालर में 15.85 प्रतिशत और रुपयों में 9.89 प्रतिशत की गिरावट आयी है। गैर पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में भी मार्च 2016 में और अप्रैल–मार्च 2015–16 में भी गिरावट आयी है। मार्च–2016 में यह गिरावट 8.49 प्रतिशत की थी, जबकि विगत वित्तीय वर्ष के 12 महीनों की अवधि में यह गिरावट 8.52 प्रतिशत की थी।

अप्रैल 1, 2015 को देश के लिए वर्ष 2015–2016 से 2020–2021 की अवधि के लिए घोषित नई विदेश व्यापार नीति में देश के कुल निर्यात बढ़ाकर दुगुने करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इसके विपरीत विगत 16 महीनों से निर्यात में आ रही निरंतर गिरावट चिंता का कारण है। निर्यातों में ऐसी गिरावट विश्व की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी देखी जा सकती है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2016 में पिछले वर्ष के जनवरी माह की तुलना में अमरीकी निर्यातों में 10.81 प्रतिशत, यूरोपीय संघ के निर्यातों में 7.4 प्रतिशत, चीन के निर्यातों में 11.37 प्रतिशत और जापान के निर्यातों में 12.85 प्रतिशत

*विश्व में फैल रही आर्थिक मंदी का प्रभाव हमारी सेवाओं के निर्यात पर भी हुआ है। रिजर्व बैंक के 18 अप्रैल 2016 के प्रेस रिलीज के अनुसार अप्रैल–फरवरी 2015-16, 11 महीनों की अवधि में देश का सेवाओं का निर्यात 64.60 अरब डालर रहा है। जबकि वर्ष 2014-2015 की इसी अवधि में भारत के सेवाओं की निर्यात 69.13 अरब डालर रहे है।*

**– प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

की गिरावट आयी है। भारत के निर्यातों में विगत वर्ष के जनवरी माह की तुलना में जनवरी 2016 में 13.6 प्रतिशत की गिरावट आयी है, जो कि अमरीका, यूरोप व चीन की तुलना में सर्वाधिक है। दूसरी ओर मार्च 2016 से चीन के निर्यातों में पुनः वृद्धि का दौर प्रारंभ हो गया है। मार्च 2016 में तो चीन के निर्यातों में 18.7 प्रतिशत की एवं अप्रैल 2016 में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत भारत के निर्यातों में 16 माह से आ रही गिरावट के क्रम में मार्च 2016 में भी 5.5 प्रतिशत की गिरावट जारी रही है जो चिंताकारक है।

इस संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विशेष राहत की बात यह है कि हमारे आयातों में निर्यात की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट आयी है। इसके फलस्वरूप 2015–2016 के व्यापार घाटे में भी कमी आयी है। मार्च–2016 में हमारे आयात 27.28 अरब डालर (186250.88 करोड़ रुपये) के ही थे जो मार्च 2015 की तुलना में डालर में 21.56 प्रतिशत और रुपयों में 15.82 प्रतिशत कम थे। अप्रैल–मार्च 2015–16 की 12 महीनें की अवधि में हमारे आयात 379.6 अरब डालर थे। जो अप्रैल–मार्च 2014–2015 में 448 अरब डालर के थे। इस प्रकार विगत वित्तीय वर्ष 2014–15 की तुलना में डालर में 15.28 प्रतिशत व रुपयों में 9.34 प्रतिशत की गिरावट आई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत का व्यापार घाटा 118.45 अरब डालर रहने की अपेक्षा है जो 2014–15 के 137.69 अरब डालर के व्यापार घाटे से काफी कम है।

इसी क्रम में विश्व में फैल रही आर्थिक मंदी का प्रभाव हमारी सेवाओं के निर्यात पर भी हुआ है। रिजर्व बैंक के 18 अप्रैल 2016 के प्रेस रिलीज के अनुसार अप्रैल–फरवरी 2015–16, 11 महीनों की अवधि में देश का सेवाओं का निर्यात 64.60 अरब डालर रहा है। जबकि वर्ष 2014–2015 की इसी अवधि में भारत के सेवाओं की निर्यात 69.13 अरब डालर रहे है। इसलिए सेवाओं और वस्तुओं के समग्र व्यापार की दृष्टि से देश का कुल व्यापार घाटा वर्ष 2015–2016 में 53.85 अरब डालर रहने की अपेक्षा है जो वर्ष 2014–2015 में और भी उच्च 68.55 अरब डालर रहा है। देश के व्यापार घाटे की इतनी बड़ी राशि के उपरांत भी विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले 69 अरब डालर की प्राप्ति से इस विगत वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भ।डारों में 16 अरब डालर की वृद्धि ही हुई है। इस प्रकार भारी व्यापार घाटे के उपरांत भी देश की अर्थव्यवस्था आज विदेशों में कार्यरत भारतीयों के कारण बची भुगतान संतुलन की दृष्टि से निष्पद है। लेकिन यदि अप्रैल 2015 में घोषित हमारी नई व्यापार नीति के अनुरूप निर्यातों को दुगुना करना है तो इसके लिए हमें निर्यात वृद्धि की नवीन रणनीति की रचना करनी होगी।

**चीन के विदेशी व्यापार का सरप्लस 45 अरब डालर था, जबकि मार्च 2016 के हमारे कुल निर्यात ही 22.71 अरब डालर के थे एवं उसमें भी 4.57 अरब डालर का घाटा था।**

वैसे भी हम विदेशी व्यापार में अनवरत घाटे को कब तक जारी रहने देंगे। देश की प्रतिभा विदेशों से जो धन का निजी अंतरण करती है, वह हमारे सुरक्षा चक्र का आधार है। हम स्वस्थ आर्थिक, औद्योगिक व व्यापार नीतियों से कब व्यापार घाटे से उबरेंगे? यह 25 वर्षों के आर्थिक सुधारों के बाद भी एक गंभीर यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हम अनेक अवसरों पर जब चीन व भारत की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करते समय यह भूल जाते हैं कि अप्रैल 2016 में चीन के विदेशी व्यापार का सरप्लस 45 अरब डालर था, जबकि मार्च 2016 के हमारे कुल निर्यात ही 22.71 अरब डालर के थे एवं उसमें भी 4.57 अरब डालर का घाटा था। हमारे आज के मासिक व्यापार घाटे का दस गुना आज चीन का मासिक व्यापार अतिरेक अर्थात ट्रेड सरप्लस है। वर्ष 2015–16 में हमारे कुल निर्यात 261 अरब डालर व उसमें भी 116 अरब डालर का घाटा रहा है। दूसरी ओर चीन के 2015 के विदेश व्यापार में 595 अरब डालर का सरप्लस या मुनाफा रहा है और कुल निर्यात (वस्तु + सेवा निर्यात) 2375 अरब डालर के (भारत के कुल निर्यातों के 7 गुने) रहे हैं। इसमें चीन के सेवाओं के कुल निर्यात 288 अरब डालर के रहे हैं। हमारे वस्तु निर्यात 261 अरब डालर व सेवाओं के निर्यात 70 अरब डालर के हैं। इसलिये अब 1991 से चल रहे आर्थिक सुधारों के 25 वर्ष पूरे हो जाने पर तो हमें अपनी नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के परिणामों की भी समीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिये।

विश्वभर में आर्थिक मंदी के उपरांत भी चीन ने मार्च–2016 में 18.7 प्रतिशत व अप्रैल में 4 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि अर्जित की है। वहीं चीन ने मार्च 2016 में अपने निर्यातों की 1.7 प्रतिशत की कटौती की है। इस प्रकार मार्च 2016 में जहां भारत का व्यापार घाटा 5.1 अरब डालर का रहा है। वहीं चीन के विदेशी व्यापार में मार्च 2016 में 29.9 अरब डालर (194.6 अरब युआन) व अप्रैल 2016 में 45.9 अरब डालर का अतिरेक या मुनाफा रहा है। चूंकि भारत का सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ रहा है। इसलिए देश को अपने व्यापार घाटे पर नियंत्रण के लिए प्रयास करने के क्रम में सर्वप्रथम चीन के साथ बढ़ रहे व्यापार घाटे पर नियंत्रण करना चाहिये।

## चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा अत्यधिक चुनौतीपूर्ण

देश का सर्वाधिक व्यापार घाटा आज चीन के साथ है, जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। वर्ष 2015 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51.9 अरब डालर पर पहुंच गया है। यह देश के कुल व्यापार घाटे का 45 प्रतिशत है। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि भारत से चीन को होने वाले निर्यात मात्र 9.6 अरब डालर के हैं जबकि भारत में चीन के निर्यात इसके पौने सात गुने, अर्थात् 61.5 अरब डालर के हैं। इसलिए चीन के साथ भारत के कुल 71.22 अरब डालर के व्यापार में 51.8 अरब डॉलर का घाटा है। भारत से चीन को होने वाले निर्यातों में भी कच्चे माल की ही अधिकता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा कच्चे खनिज लोहे की है। दूसरी ओर भारत को होने वाले चीन के सारे निर्यात विनिर्मित वस्तुओं के हैं। ऐसा द्विपक्षीय व्यापार असंतुलन विश्व में कहीं भी दो व्यापारिक साझोदारों में नहीं है। वह भी तब, जबकि चीन हमारे साथ निरंतर शत्रुवत व्यवहार करता रहा है। चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण ही देश में आज बड़े पैमाने पर उद्योग बंद होते जा रहे हैं। देश में बैंकिंग क्षेत्र की अनिष्पादनीय आस्तियों (Non Performing Assets) में भारी वृद्धि का भी सबसे बड़ा कारण चीन से निरंकुश गति से बढ़ रहे आयातों से फैल रही औद्योगिक रूग्णता है। आज लिखने के पेन व बल्ब से लेकर पर्सनल कम्पयूटर्स (P.C.), मोबाईल फोन, बिजली के साज सामान और सौर ऊर्जा संयंत्रों तक सभी उद्योग वर्गों में बढ़ रहे चीनी आयातों की वृद्धि से ही देश में उद्यम बंदी, डी इण्डस्ट्रेलाईजेशन और अनिष्पादनीय आस्तियों में वृद्धि हो रही है। देश की वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भी चीन से बढ़ रहे आयातों के कारण देश के सूक्ष्म लघु व मध्यम आकार के उद्यम (MSME) सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनके द्वारा संसद में दिए उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित 12 प्रमुख उत्पाद समूहों में वर्ष 2011–12 से 2014–15 के बीच, चीन से होने वाले आयातों की वृद्धि शेष विश्व के सभी देशों से हुई संयुक्त आयात वृद्धि की तुलना में भी सर्वाधिक है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वर्तमान में चल रहे 322 राशिपतन–रोधी मामलों (Anti Dumping Cases) में सर्वाधिक 177 मामले चीन से संबंधित है।

सर्वाधिक आश्चर्यजनक तो यह है कि एक ओर तो देश के अधिकांश सौर ऊर्जा संयंत्रों के विनिर्माणी उद्यमों की प्रगति अवरूद्ध हो रही है और वे रूग्ण होते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर पूरे देश में चीनी सौर ऊर्जा पेनल्स व संयंत्रों का आयात तेजी से बढ़ रहा है। आज देश में 80 प्रतिशत सोलर पेनल चीन से ही आ रहे हैं। कई स्थानों पर सोलर पार्क लगाने के ठेके भी चीनी कंपनियों को ही जा रहे हैं। इसके कारण आगामी वर्षों में चीनी कंपनियां भारी मात्रा में देश से विदेशी मुद्रा बाहर ले जायेंगी। अमरीका तक को उसके घरेलू उद्यमों को बचाने के लिए चीनी सोलर पेनल्स पर 238 प्रतिशत तक की एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगानी पड़ी है। भारत में भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सस्ती डम्पिंग की शिकायत मिलने के संबंध में अनुसंधान करने पर डम्पिंग अर्थात् राशिपतन के प्रमाण पाये गये हैं व ऐसा पाये जाने पर राशिपतन रोधी (एण्टी–डम्पिंग) शुल्क लगाने की अनुशंसा भी की गई थी। लेकिन, वित्त मंत्रालय ने जानबूझकर निर्धारित अवधि में एंटीडंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का निर्णय ले लिया। इससे देश में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय उद्यमों को भारी धक्का लगा है। इसलिए अब चीन मलेशिया, ताईवान, अमेरिका व यूरोप की सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादक कंपनियां भारी मात्रा में सस्ती डंपिंग कर भारतीय उत्पादकों को नुकसान पहुंचा रही हैं।

**वर्ष 2015 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51.9 अरब डालर पर पहुंच गया है। यह देश के कुल व्यापार घाटे का 45 प्रतिशत है।**

यहीं स्थिति देश में बस व ट्रक टायर उत्पादकों की भी हो रही है। टायर उद्योगों के संघ के अनुसार विगत 2 वर्षों में देश में बस व ट्रक के रेडियल टायरों के आयात में 2.5 गुनी वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2014 में देश में बस व ट्रक रेडियल्स का मासिक आयात 40 हजार टायर था जो वित्तीय वर्ष 2014–15 में बढ़कर 65 हजार टायर प्रतिमाह हो गया और 2015–16 में 1 लाख टायर प्रतिमाह हो गया। देश में टायरों का अधिकांश आयात चीन से ही हो रहा है। टायरों के कुल आयात में चीनी टायरों का अनुपात एक ही वर्ष में 2 गुना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में देश में होने वाले कुल आयातों में चीन का अंश 40 प्रतिशत था। 2015–16 में बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है। आज देश में बस व ट्रक टायरों की कुल मांग (Replacement Demand) की 30–40 प्रतिशत की पूर्ति चीनी टायरों से हो रही है। इसके कारण देश में टायर उद्योग रूग्ण व समस्याग्रस्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में ही बस व ट्रक टायरों का आयात 7.8 लाख वार्षिक आयात से बढ़कर 12.8 लाख टायर प्रतिवर्ष हो गया है जो 2013–14 में मात्र 4.9 लाख टायरों का ही था। इस प्रकार ट्रक व

बस टायरों का आयात एक वर्ष में ही 64 प्रतिशत बढ़ गया है। अमरीका तक ने चीनी आयातों से घरेलू टायर उद्योग बचाने के लिए अत्यंत ऊंचा राशि पतन रोधी शुल्क और अनुदान संतुल्यकारी शुल्क लगाया है। इसके कारण देश में रबर उत्पादक भी प्रभावित हो रहे है।

**मोबाईल फोन के बाजार पर भी चीनी कंपनियों का फैलता साम्राज्य**

देश के अन्य सभी उद्योगों के साथ–साथ अब स्मार्ट फोन के बाजार पर भी चीनी कंपनियों का ही साम्राज्य फैल रहा है। कंट्री पाइंट टैक्नालाजी रिसर्च नामक अनुसंधान के अनुसार वर्ष 2013 की प्रथम तिमाही में देश में चीनी स्मार्ट फोन के मात्र 12 ब्रांड उपलब्ध चलन में थे जिनकी संख्या 2015 की प्रथम तिमाही तक बढ़कर 57 हो गयी। इस प्रकार 2 वर्ष में ही भारतीय बाजारों में चीनी ब्रांडों की संख्या 12 से बढ़कर 57 अर्थात् पौने पांच गुनी हो गयी है। भारत के स्मार्ट फोन के बाजार में चीनी ब्रांडों का हिस्सा 2014 में मात्र 15 प्रतिशत था जो बढ़कर 2015 में 22 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 24.4 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर स्मार्ट फोन के भारतीय ब्रांडों का बाजार अंश 5 प्रतिशत घट गया है। चीनी ब्रांडों के दबाव में अन्य वैश्विक ब्रांडों का बाजार अंश भी 1 प्रतिशत घटा है। स्मार्ट फोन के चीनी ब्रांडों यथा हुवेई, लिनोवो, मोटो, जिओमी, जिओनी, वन प्लस, वेगो, ओप्पो, मिजु, लिको, पूल पेड आदि की बिक्री भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ रही है। इसी प्रकार देश का बिजली का बल्ब उद्योग, कांच उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग, फर्नीचर उद्योग आदि सभी उद्योग चीनी आयातों से प्रभावित हुए हैं।

चीन से इस बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए उस पर नियंत्रण के लिए चीनी कंपनियों को देश में निवेश व उत्पादन की सुविधाएं देने का प्रस्ताव और भी घातक है। चीनी आयातों पर अंकुश लगाने के कई विधि सम्मत मार्ग हैं लेकिन, चीन के द्वारा देश में एक बार निवेश कर लेने के उपरांत उन क्षेत्रों से उसे वापस लौटाना कभी भी संभव नहीं होगा। चीनी उद्यमों द्वारा अपने इस निवेश के लाभों के पुनिर्निवेश से और लाभों को देश से बाहर ले जाने से कई नयी समस्याएं खड़ी होगी। इसलिये देश के विदेश व्यापार में घाटे पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चीनी आयातों पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके विपरीत चीन को इन उत्पादों के देश में उत्पादन की सुविधा देना तो और भी खतरनाक है। इसलिये विदेश व्यापार में घाटे पर अंकुश लगाने के लिए चीन से हो रही निरंकुश आयात वृद्धि पर तत्काल प्रभावी रोक अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु आयातित वस्तुओं के संबंध में गुणवत्ता के राष्ट्रीय प्रमाप भी स्थापित किये जाने चाहिये। इनके अतिरिक्त समयोचित राशिपतन रोधी (एंटी डंपिंग) शुल्क और अनुदान समतुल्यकारी शुल्क (काउंटर वेलिंग ड्यूटी) भी समुचित मात्रा में लगायी जानी चाहिये। देश के व्यापार घाटे में नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम चीन के साथ बढ़ रहे व्यापार घाटे पर तत्काल नियंत्रण आवश्यक है। ❑❑


## पंजीकरण का प्रमाण पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| अखबार का शीर्षक | | : | **स्वदेशी पत्रिका** |
| अखबार का पंजीकरण नंबर | | : | DL/SW/1/4074/2015-16-17 |
| भाषा/बोली जिसमें प्रकाशित किया है | | : | **हिन्दी** |
| प्रकाशन की अवधि/दिन/तारीख, जिस पर इसे प्रकाशित किया। | | : | **मासिक** |
| समाचार पत्र का खुदरा मूल्य | | : | **15 रू.** |
| **प्रकाशक** का | नाम | : | **ईश्वरदास महाजन** |
| | राष्ट्रीयता | : | **भारतीय** |
| | पता | : | **धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110022** |
| **मुद्रक** का | नाम | : | **कॉम्पीटेंट बिंडर्स** |
| | राष्ट्रीयता | : | **भारतीय** |
| | पता | : | **नवीन शाहदरा, दिल्ली–110032** |
| **संपादक** का | नाम | : | **विक्रम उपाध्याय** |
| | राष्ट्रीयता | : | **भारतीय** |
| | पता | : | **धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110022** |
| **मुद्रण परिसर का पता** | | : | **धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110022** |
| **प्रकाशन स्थान** | | : | **धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110022** |

# सूखा पीड़ितों के प्रति संवेदना

**एक समय** जब पूरा देश खाद्य संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सोमवार को उपवास करने का आग्रह किया था। वह 1965 का साल था, जब सूखा पड़ा था और तब भारत खाद्यान्न आयात पर निर्भर था। तब देश में हर आदमी भूखा नहीं सोता था, पर उपवास के लिए शास्त्री जी का आह्वान मुख्यतः लाखों भूखे लोगों के प्रति एकजुटता की अभिव्यक्ति थी। मुझे नहीं लगता कि उपवास से जितना खाद्यान्न बचाया गया, वह आबादी के एक छोटे–से हिस्से को भी खिलाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसमें अंतर्निहित संदेश स्पष्ट था–राष्ट्र को अपने लोगों की परवाह थी और वह एक दिन का भोजन छोड़ने के लिए भी तैयार था, ताकि उसे भूखे लोगों के साथ साझा किया जा सके।

पचास वर्ष बाद बॉम्बे हाई कोर्ट को यह निर्देश देने की जरूरत पड़ी कि जल संकट से जूझ रहे लोगों के हित में आईपीएल के 13 मैचों को सूखाग्रस्त महाराष्ट्र से बाहर आयोजित किया जाए। हाई कोर्ट निश्चित रूप से जानता था कि क्रिकेट पिच पर इस्तेमाल होने वाला पानी बचाकर जल संकट से जूझ रहे शहरों में से लातूर जैसे एक शहर की जरूरत भी पूरी नहीं की जा सकती, पर इस निर्देश का उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार को एक सख्त संदेश देना था कि वह 'लोगों की दुर्दशा की अनदेखी नहीं कर सकती।' इसके बाद मुंबई के होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन ने भी घोषणा की कि वह अपने ग्राहकों से अपील करेगा कि वे जब रेस्तरां में आएं, तो यह अपेक्षा न करें कि उन्हें जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे आधा गिलास पानी छोड़कर नहीं उठें। इस कदम से भी सूखाग्रस्त महाराष्ट्र के लोगों की प्यास नहीं बुझेगी, पर यह साथी नागरिकों द्वारा झेले जा रहे मुश्किलों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है।

जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय सूखाग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं और दुर्दशा के प्रति सरकार को जगाकर दिखाए कि प्रशासन कितना संवेदनहीन बन गया

*जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय सूखाग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं और दुर्दशा के प्रति सरकार को जगाकर दिखाए कि प्रशासन कितना संवेदनहीन बन गया है। एक अनुमान के मुताबिक, 35 करोड़ लोग गंभीर सूखे की चपेट में हैं, लेकिन सरकार और मुख्यधारा के मीडिया का एक हिस्सा इस गंभीर संकट से बेखबर था।*

**– देविंदर शर्मा**

है। एक अनुमान के मुताबिक, 35 करोड़ लोग गंभीर सूखे की चपेट में हैं, लेकिन सरकार और मुख्यधारा के मीडिया का एक हिस्सा इस गंभीर संकट से बेखबर था। दस राज्यों की बड़ी आबादी सूखे की चपेट में है। लगातार सूखे की मार से फसलें सूख गई हैं, किसानों ने पहले अपने पशुओं को त्यागा, फिर संकट बढ़ने पर पलायन के लिए मजबूर हुए।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा समेत कई क्षेत्रों में लगातार तीसरे वर्ष सूखा पड़ा है। महाराष्ट्र ने अपने कुल करीब 43,000 गांवों में से 14,708 गांवों को विगत अक्तूबर में ही सूखाग्रस्त घोषित किया था, जबकि कर्नाटक के 30 में से 27 जिलों के 127 ताल्लुका में विगत सितंबर में सूखा घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश के 196 मंडलों में सूखा घोषित किया गया है। पिछले छह वर्षों में झारखंड का पलामू जिला लगातार पांचवें वर्ष सूखे का सामना कर रहा है।

बुंदेलखंड में भी यही स्थिति है। सूखे की चपेट में आए लोगों के चेहरे दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। कम से कम पिछले चार वर्षों से बुंदेलखंड से सूखे की खबरें आ रही हैं। जब सूखे का दबाव पड़ता है, तो इसकी मार सबसे पहले पशुओं पर पड़ती है। महिलाएं पशुओं के माथे पर तिलक कर, उनका पैर छूकर उन्हें खुला छोड़ देती हैं। उसके बाद जब सूखे की स्थिति और भयानक होती है, तो पेयजल के स्रोत सूख जाते हैं। लोग अपना ज्यादातर समय मटका भर पानी इकट्ठा करने में बिताते हैं। और जब फसलें सूख जाती हैं, तो किसानों के सामने पलायन ही एकमात्र विकल्प बचता है।

महाराष्ट्र के लातूर में, जहां टैंकरों से पानी की आपूर्ति होती है, धारा 144 लागू करने की खबर यही दर्शाती है कि पेयजल की कमी से कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। कपड़े धोने, स्नान जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पानी

**मौजूदा गंभीर संकट के समय राष्ट्र को उस बड़ी आबादी के साथ एकजुट खड़ा होना चाहिए, जो एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है।**

उपलब्ध न होने से लोगों की मुश्किलें भयावह हो गई हैं। शहरों में रहने वाले लोगों को, जिन्हें नल खोलते ही पानी मिल जाता है और अपनी इच्छा से रेफ्रीजरेटर से ठंडा पानी निकालकर पी सकते हैं, नहीं मालूम कि जब दिन भर पानी नहीं मिलता, तो जीवन कितना कठिन हो जाता है! हाल ही में मैं बुंदेलखंड में एक किसान के घर गया था। मैंने जब स्नान करने की इच्छा जताई, तो परिवार की एक महिला ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, आप चाहें तो एक और लड्डू खा लें, लेकिन स्नान के लिए न कहें।

पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर सूखाग्रस्त राज्यों का दौरा करने के बाद वहां की असमानता को देखकर मैं चकित हूं। कर्नाटक की राजधानी में गंभीर सूखे का कोई संकेत नहीं है, जबकि राज्य के 80 फीसदी से ज्यादा इलाके सूखे से प्रभावित हैं। इसी तरह मुंबई से गुजरते हुए गंभीर जल संकट का थोड़ा–सा भी आभास आपको नहीं होगा, जिससे पिछले दो वर्षों से राज्य जूझ रहा है।

मौजूदा गंभीर संकट के समय राष्ट्र को उस बड़ी आबादी के साथ एकजुट खड़ा होना चाहिए, जो एक–एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। मुंबई की रेस्तराओं की तरह मैं उम्मीद करता हूं कि पांच सितारा समेत सभी होटल पानी की खपत को घटाने के लिए तत्काल उपायों की घोषणा करेंगे। कम से कम वे अपने ग्राहकों को स्नान के लिए बाथटब का इस्तेमाल बंद कर केवल शॉवर का उपयोग करने के लिए तो कह ही सकते हैं। संकट की अवधि तक स्विमिंग पूलों को भी बंद रखना चाहिए। कारों की धुलाई और बगीचों की सिंचाई पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। जल संरक्षण के लिए स्कूल–कॉलेजों और सरकारी प्रतिष्ठानों को भी कदम उठाने की जरूरत है। सूखा प्राकृतिक आपदा है और राष्ट्र को इससे प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। पानी का बेजा इस्तेमाल किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि आज अगर लालबहादुर शास्त्री जीवित होते, तो क्या वह संवेदनशून्य राष्ट्र के आगे करुणा की गुहार लगाते। ❑❑

लेखक कृषि व्यापार एवं नीति के विशेषज्ञ है।

# रूपए को मजबूत करने की जरूरत

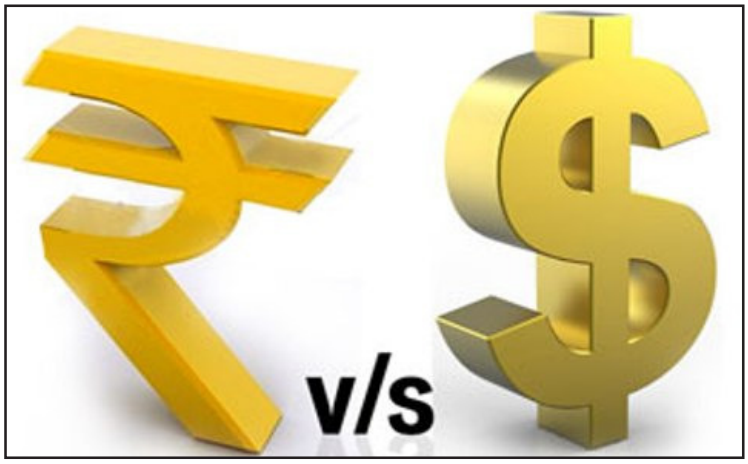


**किसी भी देश** की ताकत का अंदाज उसकी करैंसी के मूल्य से होता है। यदि उसकी करैंसी मजबूत है तो देश मजबूत कहलाएगा और करेंसी यदि कमजोर है, तो देश भी कमजोर ही कहा जाएगा, हालांकि कई बार कुछ लोगों, विशेषतौर पर निर्यातकों का यह तर्क होता है कि करेंसी को कमजोर कर हम अपने निर्यात बढ़ा सकते हैं। जब देश को आजादी मिली तो 3.3 रूपये का एक डालर हुआ करता था। समय बदला, 1966 में रूपये का पहला बड़ा अवमूल्यन हुआ और 7.5 रूपये का डालर हो गया। यह विनिमय दर दशकों तक चली, लेकिन उदारीकरण और भूमंडलीकरण के युग में वर्ष 1981–82 में जब रूपये का अवमूल्यन होना शुरू हुआ तो यह प्रक्रिया कभी थमी नहीं। 1985 में 12.38 रूपये का डालर था और रूपया लगातार कमजोर होते हुए अगस्त 2013 तक 68.84 प्रति डालर तक पहुंच गया। बीच में रूपए में कुछ सुधार हुआ, लेकिन हाल ही में फरवरी 2016 में फिर से विनिमय दर 68.82 रूपये प्रति डालर तक पहुंचने के बाद मई 2, 2016 तक सुधरकर रूपया फिर से 66.44 रूपए प्रति डालर तक ही पहुंचा।

*किसी भी देश की करेंसी का मूल्य उस देश में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से तय होता है। यानि भारत में डालर के मुकाबले रूपए का मूल्य डालरों की मांग और पूर्ति से तय होगा। भूमंडलीकरण के बाद लगातार बढ़ते आयातों और उसके अपेक्षाकत कहीं कम बढ़ते निर्यातों के चलते देश में डालरों की मांग लगातार बढ़ती गई।*

**– डॉ. अश्वनी महाजन**

किसी भी देश की करेंसी का मूल्य उस देश में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से तय होता है। यानि भारत में डालर के मुकाबले रूपए का मूल्य डालरों की मांग और पूर्ति से तय होगा। भूमंडलीकरण के बाद लगातार बढ़ते आयातों और उसके अपेक्षाकृत कहीं कम बढ़ते निर्यातों के चलते देश में डालरों की मांग लगातार बढ़ती गई। व्यापार घाटे को पूरी तरह से पाटने में हमारे सॉफ्टवेयर के निर्यात और अप्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि भी अपर्याप्त ही सिद्ध हुई। ऐसे में विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियों निवेश दोनों) के द्वारा भुगतान शेष के घाटे को चुकाने के लिए उपयोग किया जाने लगा। लेकिन डालरों की मांग और पूर्ति के असंतुलन के कारण हमारा रूपया लगातार कमजोर होता गया और भूमंडलीकरण की शुरूआत (1990) में 17 रूपए का एक डालर था, जो आज 66.44 रूपए प्रति डालर पर है।

## क्यों हुआ रूपया कमजोर?

असलियत यह है कि 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद आयातों पर लगे तमाम प्रतिबंध समाप्त हो गए, टैरिफ घटा दिए गए और 1995 में विश्व व्यापार संगठन के समझौतों को अमल में लाने के बाद तो अब यह स्थिति है कि आयातों पर टैरिफ और गैर–टैरिफ बाधाएं लगाने की संभावनाएं प्रायः समाप्त हो गई। इसके कारण हमारे आयातों में अवभूतपूर्व वृद्धि होनी शुरू हो गई। 1990–91 में हमारे कुल आयात मात्र 24.1 अरब डालर के ही थी, जो बढ़ते हुए 2012–13 में 490.7 अरब डालर तक पहुंच गए, यानि इस दौरान आयातों में 15 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर्ज हुई। दूसरी ओर निर्यातों में वृद्धि मात्र 13.6 प्रतिशत

वार्षिक की रही। निर्यातों के मुकाबले आयातों में भारी वृद्धि होने के कारण हमारा व्यापार शेष 1990–91 में 5.9 अरब डालर से बढ़ता हुआ 2012–13 में 190.3 अरब डालर रिकार्ड किया गया। इसी प्रकार चालू खाते पर हमारा भुगतान शेष घाटा 2012–13 में 88.2 अरब डालर पहुंच गया।

### अब रूपए की कमजोरी का नहीं है कोई कारण!

लेकिन पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम तेल की घटती कीमतों, सोने के आयातों पर लगे अंकुशों आदि के चलते हमारे आयात घट रहे हैं और इस कारण हमारा व्यापार शेष घाटा 2012–13 में 190.4 अरब से घटता हुआ 2014–15 में 137.0 अरब डालर तक पहुंच गया। लेकिन उसके बावजूद 2012–13 में 54.4 रूपए प्रति डालर से 2014–15 में 62.6 रूपए प्रति डालर तक पहुंच गया। अगस्त 2013–14 की पहली छमाही में भुगतान शेष की कठिनाइयों के चलते रूपया अगस्त 28, 2013 को रिकार्ड न्यूनतम स्तर 68.84 रूपए तक पहुंच गया। उसके बाद कुछ सुधरते हुए 2014–15 तक रूपया 62.6 रूपए प्रति डालर तक पहुंचा। 2015–16 में परिस्थितियां और भी सुधरी और अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2015–16 में हमारा भुगतान शेष का घाटा 18.4 अरब अरब डालर तक पहुंच रहा है। यही नहीं जनवरी और मार्च की तिमाही में तो भुगतान शेष 3 अरब डालर सरप्लस में पहुंच गया है। लेकिन खेद का विषय यह है कि उसके बावजूद हमारा रूपया लगातार कमजोर होता जा रहा है और फरवरी 2016 तक 68.8 रूपए प्रति डालर के स्तर पर पहुंच गया। यही नहीं 2015 में तो विदेशी निवेश भी रिकार्ड स्तर (39.3 अरब डालर) पर पहुंच गया है। बेहतर होती भुगतान स्थितियों के चलते रूपए का अभी भी कमजोर होना आश्चर्यजनक लगता है।

### पोर्टफोलियो निवेशकों की भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ती ग्रोथ और कहीं बेहतर आर्थिक स्थिति के बावजूद चीन में आर्थिक और शेयर बाजारों की उथल–पुथल के चलते पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा शेयर बाजारों में भारी बिकवाली और निवेश के बर्हिगमन के कारण रूपए पर अचानक दबाव बनता है। देखने में आया है कि जब–जब पोर्टफोलियो निवेशक बिकवाली कर पैसा (डालर) बाहर भेजते हैं, तब–तब रूपया कमजोर हो जाता है।

**रूपया यदि कमजोर हो जाये तो विदेशी कर्ज और उस पर रूपयों में ब्याज की अदायगी भी बढ़ जाती है।**

आज जबकि हमारी विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति मजबूत होती जा रही है, रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आपूर्ति करके क्षणिक रूप से पोर्टफोलियो निवेश के बर्हिगमन को निष्प्रभावी बनाना संभव है। लेकिन रिजर्व बैंक सामान्यतौर पर बाजारों में हस्तक्षेप से बचने के नाम पर ऐसा नहीं करता। रिजर्व बैंक का दायित्व है कि रूपए में इस प्रकार की उथल–पुथल को निष्प्रभावी करे।

### क्या होता है कमजोर रूपये का असर?

रूपया जब कमजोर होता है, हमें प्रत्येक डालर के बदले ज्यादा रूपये चुकाने पड़ते हैं। इसके कारण सीधे–सीधे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो आम आदमी को प्रभावित करती हैं। यही हाल अन्य आयातों का है, चाहे वो तैयार माल हो, मशीनरी हो या कलपुर्जे हो। आज हम अपनी जीडीपी के लगभग 28 प्रतिशत के मुकाबले आयात करते हैं। यानि यदि आयात 10 प्रतिशत भी मंहगे हो जाये तो मंहगाई 3 प्रतिशत बढ़ जाती है।

हमें यह भी याद रखना चाहिए कि देश पर विदेशी कर्ज भी बहुत ज्यादा है। रूपया यदि कमजोर हो जाये तो विदेशी कर्ज और उस पर रूपयों में ब्याज की अदायगी भी बढ़ जाती है। इससे सरकारी बजट पर तो प्रतिकूल असर पड़ता ही है, साथ ही साथ जिन निजी फर्मों द्वारा विदेशों से उधार लिया होता है, उनके ब्याज और अदायगी की लागत भी बढ़ जाती है। इससे उनके बिजनेस को भी भारी धक्का भी लग सकता है।

### रूपए को मजबूत करने की जरूरत

निर्यातकों की हमेशा से ही यह दलील रही है कि रूपए का अधिकाधिक अवमूल्यन उनके निर्यातों के बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इसी दलील को मानते हुए पहले 1964 में रूपए का अवमूल्यन हुआ और बाद में 1983 से लेकर अब तक रूपए की कीमत लगातार घटते हुए अब 66.4 रूपए प्रति डालर तक पहुंच गई है। लेकिन यह देखा गया है कि निर्यातों के बढ़ने की दर हमेशा ही आयातों के बढ़ने की दर से कम ही रही। ऐसे में, यदि आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर सोचें, तो रूपए का अवमूल्यन करने के बजाय उसको और मजबूत करने से व्यापार घाटे को पाटा जा सकता है। यदि पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा बाहर भेजने के कारण यदि रूपए में गिरावट आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक आसानी से अपने विदेशी मुद्रा भंडार के बल पर रूपए में गिरावट को रोक सकता है और बाद में पोर्टफोलियो निवेश वापिस आने पर उसकी भरपाई कर सकता है। इसके अलावा सरकार द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अनुशासित करना भी जरूरी है। न्यूनतम तीन साल का लाक– इन–पीरियड और उनके लाभों पर टैक्स जैसे कुछ कारण हैं जो पोर्टफोलियो निवेशकों को अनुशासित कर सकते हैं। ❑❑

# संकेत तो सुहाने हैं

*सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा कम करने, व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए किये गये प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चमकता सितारा बनकर उभरा है। वित्तमंत्री निश्चित ही इसके लिए अपनी पीठ थपथपाना चाहेगें।*

**– डॉ. सुभाष शर्मा**

**राजनीतिक मोर्चे** पर जूझ रही भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत निश्चित ही सुखद है। कम होती मंहगाई, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में बढ़ोत्तरी की संभावना, मजबूत होता रुपया तथा अच्छे मानसून की भविष्यवाणी सहित कई कारण है जो दर्शा रहे है कि अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने ही वाले है।

हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की रिपोर्ट से अपनी बात शुरु करते हैं। इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 में 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि यही रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति इतनी आशावान नहीं है तथा इसमें इस वर्ष मात्र 3.2 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गयी है। अमरीका तथा चीन की वृद्धि दर भी क्रमशः 3.2 तथा 6.1 प्रतिशत ही रहने की संभावना है। जिसका अर्थ है कि भारत अगले दो वर्षों तक दुनिया की सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 2011–2014 के बीच औसतन मात्र 5.3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी, इसका 7.5 प्रतिशत से बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस रफ्तार के पीछे कारणों का विश्लेषण करते हुए तेल की कीमतों में गिरावट तथा सरकार द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन को श्रेय दिया गया है। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा कम करने, व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए किये गये प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चमकता सितारा बनकर उभरा है। वित्तमंत्री निश्चित ही इसके लिए अपनी पीठ थपथपाना चाहेगें। हालांकि अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि वृद्धि दर बढ़ने से उस देश के नागरिकों के जीवन पर कितना सार्थक असर पड़ता है। इस बहस का नतीजा कुछ भी निकले पर अभी तक का अनुभव यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार की संभावनायें बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है।

औद्योगिक उत्पादन में पिछले तीन महीने की लगातर गिरावट के बाद फरवरी में 2 प्रतिशत की वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार का एक और बड़ा संकेत है। इस वृद्धि में खनन और बिजली क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें क्रमशः 5 और 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गयी है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में किये गये संस्थागत सुधारों के परिणामस्वरुप इन दोनों ही क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी वृद्धि की अपार सम्भावनायें है। एक और विशेष बात का यहां आकलन करना जरुरी है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसाकि फर्नीचर, रेफ्रिजेटर, टी. वी. आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि शहरी और मध्यवर्गी उपभोक्ताओं में मांग बढ़ रही है। यह बढ़ रही मांग औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई सुस्ती को दूर करने में सहायक

होगी। हालांकि गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 4.2 प्रतिशत की गिरावट यह दर्शा रही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी दबाव में है तथा मांग में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही। परंतु बजटीय प्रावधानों तथा अच्छे मानसून की भविष्यवाणी के चलते ग्रामीण मांग में बढ़ोत्तरी की संभावना है।

पिछले दो वर्षों से सूखे की मार झेल रहे भारत के लिए यह राहत की बात है कि इस वर्ष भारतीय मौसम विभाग ने औसत से ज्यादा बारिश की संभावना व्यक्त की है। 1999 के बाद पहला मौका है जब औसत से ज्यादा (106 प्रतिशत) बारिश होगी। देश के किसानों के लिए ये सबसे बड़ी खुश खबरी है क्योंकि इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों की आय बढ़ेगी। परिणामस्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त मांग पैदा होगी। कृषि क्षेत्र में 7–8 प्रतिशत वृद्धि की संभावना व्यक्त

**अच्छे मानसून की संभावना सोने पे सुहागा साबित होने वाली है क्योंकि इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में और कमी होने की संभावना है।**

की जा रही है जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद साबित होगी। हाल ही में वित्तमंत्री ने भी आशा प्रकट की है कि अच्छे मानसून से भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से आगे बढ़ सकती है।

आम आदमी को अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सरोकार मंहगाई से होता है। मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.83 प्रतिशत पर आ गया है, जो पिछले 6 महीने में सबसे कम है हालांकि रिजर्व बैंक ने 2017 के अंत तक इसको 5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा था। मंहगाई में यह कमी आम आदमी को इसलिए भी ज्यादा राहत देने वाली है क्योंकि सब्जियों में 0.54 प्रतिशत, दूध में 3.3 प्रतिशत तथा खाद्य तेल में 4.85 प्रतिशत की दर से ही कीमतें बढ़ रही है। फलों में तो यह वृद्धि निगेटिव (–1.10 प्रतिशत) है, जिसका अर्थ है कि कीमतें कम हो रही है। जिस देश में पिछले कई वर्षों से मंहगाई का सूचकांक 10 प्रतिशत से ज्यादा रहा हो वहां यह कमी इस बात की सूचक है कि अब गरीब आदमी की थाली में ज्यादा भोज्य पदार्थ आ सकते है। अच्छे मानसून की संभावना सोने पे सुहागा साबित होने वाली है क्योंकि इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में और कमी होने की संभावना है। विपक्षी दल और आलोचक अच्छे दिन के नारे को जुमला बताकर नरेंद्र मोदी को लगातार निशाना बनाते रहे हैं परंतु अर्थव्यवस्था में आई तेजी देश के लिए अच्छे दिनों की आहट का संदेश है। ❑❑


## :: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
**http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

### सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

| स्वदेशी पत्रिका | वार्षिक | आजीवन |
|---|---|---|
| हिन्दी | 150 रुपए | 1500/– रुपए |
| अंग्रेजी | 150 रुपए | 1500/– रुपए |

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

**स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

# रोजगारपरक टैक्स प्रणाली बनें

**संयुक्त राष्ट्र विकास** कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारत में बेरोजगारी की समस्या गहराती जाएगी। पिछले दो दशक में भारत में तीव्र आर्थिक विकास हुआ था। इस अवधि में 30 करोड़ युवाओं ने प्रवेश किया। तीव्र विकास के बावजूद इनमें आधों को ही रोजगार मिल सका है। ये सीमित रोजगार भी मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में मिले जैसे रिक्शा चलाने में अथवा कन्सट्रक्शन क्षेत्र में। ऐसे हालात उस समय थे जब अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास हो रहा था। वर्तमान समय में आर्थिक विकास दर घट रही है इसलिए रोजगार कम ही उत्पन्न होंगे और समस्या गहराएगी।

यूनडीपी ने सुझाव दिया है कि भारत को चीन की तरह मैनूफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। चीन ने मैनूफैक्चरिंग में वृद्धि के बल पर भारी संख्या में रोजगार बनाए थे। चीन ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया था। इन कंपनियों ने चीन में कारखाने लगाए। चीन में माल का उत्पादन करके पूरी दुनिया को माल सप्लाई किया था। चीन की स्ट्रैटेजी के वर्तमान समय में सफल होने में संदेह है। चीन ने मैनूफैक्चरिंग का विस्तार अस्सी एवं नब्बे के दशक में किया था। उस समय विकसित देशों में नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा था। उनकी अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही थी। उनके श्रमिकों को नए हाईटेक क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा था और वे चीन में बने माल को खरीद रहे थे। वर्तमान समय में विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में है। तकनीकी आविष्कारों में ठहराव आ गया है। स्पेन तथा ग्रीस के आधे कर्मी बेरोजगार है। अमरीका में रोजगार उत्पन्न होने का भ्रामक दावा किया जा रहा है। वास्तव में अमरीका में रोजगार स्वास्थ एवं शिक्षा के क्षेत्र में बन रहे है। सरकार इन क्षेत्रों में खर्च बढ़ा रही है। जैसे राष्ट्रपति ओबामा ने स्वास्थ बीमा योजना को लागू किया है। अमरीका में रोजगार का यह बनना अपने देश में मनेरगा में बन रहे रोजगार की तरह है। अमरीकी बाजार में

*वर्तमान समय में विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में है। तकनीकी आविष्कारों में ठहराव आ गया है। स्पेन तथा ग्रीस के आधे कर्मी बेरोजगार है। अमरीका में रोजगार उत्पन्न होने का भ्रामक दावा किया जा रहा है।*

**– डॉ. भरत झुनझुनवाला**

रोजगार सिकुड़ रहे है।

पूरी दुनिया में रोजगार के सिकुड़ने का कारण विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास के साथ–2 पूंजी की उपलब्धता बढ़ती जाती है और ब्याज दर कम होती जाती है। इसलिए आज विकसित देशों में ब्याज दर शून्य है। साथ–2 श्रम मंहगा होता जाता है। उनके वेतन बढ़ते है। अतः उद्यमी के लिए मशीन का उपयोग अधिक एवं श्रम का उपयोग कम करना लाभप्रद होता जाता है। यह विकास की मूल दिशा है। लेकिन तकनीकी विकास के समय विकास की यह मूल दिशा ठहर जाती है। नए उत्पादों को बनाने में नए रोजगार बनते है। जैसे पहले घोड़ागाड़ी चलती थी। फिर कार का आविष्कार हुआ। कार बनाने के कारखाने लगे। हाईवे बनाए गए। इन कार्यों के लिए कुछ समय तक श्रम की मांग बढ़ी और वेतन भी बढ़े। अमरीका आदि देशों में आज दिख रहे ऊंचे वेतन इस अल्पकालीन प्रक्रिया का परिणाम है। पिछले दो दशक में इंटरनेट के अतिरिक्त कोई आविष्कार नही हुआ है। इसलिए अब विकसित देशों में उद्यमी की श्रम का कम उपयोग करने की प्रकृति दिखने लगी है। उद्यमी द्वारा आटोमेटिक मशीन से उत्पादन अधिकाधिक किया जा रहा है। श्रम की मांग संपूर्ण विश्व में कम हो रही है। चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। हाहाकार मचा हुआ है।

इस परिस्थिति में रोजगार सृजन को सब्सिडी देकर मनेरगा जैसे कार्यक्रमों से पर्याप्त मात्रा में रोजगार बनाना कठिन होगा। रोबट के उपयोग से पहले श्रमिक को बेरोजगार किया जाएगा। फिर राबेट युक्त फैक्ट्री से टैक्स वसूल किया जाएगा। इस टैक्स से मनेरगा चलाया जाएगा। पहले बेरोजगारी के रोग को फैलाया जाएगा फिर उसका उपचार किया जाएगा। जितना लाभ मनेरगा से होगा उससे ज्यादा नुकसान राबेट से होगा इसलिए सरकार की वर्तमान पॉलिसी फेल होगी। राबेट के सामने श्रमिक नही टिक पाएगा।

समस्या के निवारण के लिए ऐसी नीति लागू करनी होगी कि उद्यमी के लिए श्रम का उपयोग करना लाभप्रद हो जाए। सुझाव है कि तमाम उद्योगों को श्रम सघनता के आधार पर श्रम–सघन एवं पूंजी–सघन क्षेत्रों में बांट दिया जाए। गणित की जाए कि एक लाख रुपए की वैल्यू बढ़ाने में

**उद्यमी द्वारा आटोमेटिक मशीन से उत्पादन अधिकाधिक किया जा रहा है। श्रम की मांग संपूर्ण विश्व में कम हो रही है।**

उद्यम द्वारा कितने श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। कोई उद्यम 100 श्रमिक का उपयोग करता पाया जाएगा तो दूसरा उद्योग 10 श्रमिक का उपयोग करता पाया जाएगा। ऐसे में 100 श्रमिक का उपयोग करने वाले उद्यम पर टैक्स कम तथा 10 श्रमिक को रोजगार देने वाले उद्यम पर टैक्स ज्यादा लगाया जा सकता है। पूंजी सघन उद्यम पर टैक्स लगाकर श्रम सघन उद्यम को सब्सिडी दी जा सकती है। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था में टैक्स की औसत दर पूर्ववत रहेगी। लेकिन उद्यमी के लिए श्रम का अधिक उपयोग करना लाभप्रद हो जाएगा। सरकारी बजट पर मनेरगा जैसे कार्यक्रमों का वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। रोजगार उत्पन्न होंगे।

श्रम के उपयोग को प्रोत्साहन देने में प्रमुख बाधा विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ की है। मान लीजिए भारत ने पूंजी सघन उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया जैसे आटोमेटिक लूम पर बनने वाले कपड़े पर टैक्स बढ़ा दिया। दूसरे देशों में आटोमेटिक लूम से बने कपड़े पर सामान्य दर से टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसे में भारत में बना कपड़ा मंहगा हो जाएगा। विदेशों से कपड़े का आयात होने लगेगा। भारत के पूँजी सघन उद्योग पिटेंगे। उनसे मिलने वाला टैक्स न्यून रह जाएगा। सरकार का बजट फेल हो जाएगा। अतः पूंजी सघन उत्पादों पर ऊंचे आयात कर भी लगाने होंगे। लेकिन डब्लूटीओ की वर्तमान व्यवस्था में पूंजी–सघन एवं श्रम–सघन माल का वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। आयात कर में भेदभाव का यह फार्मूला डब्लूटीओ के नियमों के विपरीत भी हो सकता है।

समस्या वैश्विक है। पूरी दुनिया में रोजगार का क्षरण हो रहा है। अतः सरकार को चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व श्रम संगठन, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में रोजगार के मौलिक मुद्धे को उठाए। ऐसी नीतियों को वैश्विक स्तर पर लागू करने की मांग की जाए जिससे पूरे विश्व में श्रम की मांग बढ़े। संयुक्त राष्ट्र में इस मांग को उठाने के पहले सरकार को होमवर्क करना होगा। नीति आयोग को निर्देश देना चाहिए कि रोजगार की समस्या के मौलिक समाधान का ब्लूप्रिंट देश के सामने पेश करे। ❑❑

# पुरखों के पदचिह्नों पर काश हम भी चलते

**देश में** इस समय गर्मी चरम पर है और साथ ही आजादी के बाद के भयंकरतम सूखे की त्रासदी भी विकट रूप से सामने आ रही है। ऐसी विपरीत परिस्थितयों में भी कुछ गांव–मजरे ऐसे भी हैं जो रेगिस्तान में 'नखलिस्तान' की तरह इस जलसंकट से निरापद हैं। असल में वे लोग पानी जैसी जरूरतों के लिये सरकार पर निर्भरता और प्रकृति को कोसने की आदतों से पहले ही मुक्त हो चुके थे।

ये वे लोग थे जिन्होंने आज की बड़ी–बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्रीधारी ज्ञान की बनिस्पत अपने पूर्वजों के देशज ज्ञान पर ज्यादा भरोसा किया। पानी की कमी के चले पयालन, प्रदर्शन आत्महत्या जैसी बहुत सी खबरें इस समय तैर रही हैं, लेकिन यह समय हताशा या निराशा का नहीं अपने आने वाले दिनों को पानीदार बनाने का है। जो लोग इस समय 45 डिग्री तापमान के कारण सूख गए ताल–तलैयों, नदी–नालों को संवारने में लग गए हैं वे आने वाले सालों में पानी से पैदा दिक्कतों से मुक्ति का यज्ञ कर रहे हैं।

बुंदेलखंड में ब्रितानी हुकुमत में अंग्रेजी पोलिटिकल एजेंट का मुख्यालय रहे नौगांव शहर के जब सारे नलकूप सूख गए व पानी मिलने की हर राह बंद हो गई तो वहां के समाज ने एक स्थानीय छोटी सी नदी को सहेजने का जिम्मा खुद उठा लिया। बिलहरी से निकलकर भडार तक जाने वाली कुम्हेडी नदी बीते कई–कई दशकों से गंदगी–रेत व गाद के चलते चुक गई थी। अब लोगों ने अपना चंदा जोड़ा व उसकी सफाई व उस पर एक स्टापडैम बनाने का काम शुरू कर दिया।

पन्ना के मदनसागर को अपने पारम्परिक रूप में लौटाने के लिये वहां का समाज भरी गर्मी में सारे दिन कीचड़ में उतर रहा है। सनद रहे कोई 75 एकड़ के इस तालाब का निर्माण सन् 1745 के आसपास हुआ था। इस तालाब में 56 ऐसी सुरंगे बनाई गई थीं जो शहर की

*बुंदेलखंड में ब्रितानी हुकुमत में अंग्रेजी पोलिटिकल एजेंट का मुख्यालय रहे नौगांव शहर के जब सारे नलकूप सूख गए व पानी मिलने की हर राह बंद हो गई तो वहां के समाज ने एक स्थानीय छोटी सी नदी को सहेजने का जिम्मा खुद उठा लिया।*

**– पंकज चतुर्वेदी**

बस्तियों में स्थित कुओं तक जाती थी व उन्हें लबालब रखती थीं। आधुनिकता की आंधी में ये सब चौपट हो गया था। आज यहां बच्चे अपनी बचत व जन्मदिन में मिले पैसों को इस कार्य के लिये दान कर रहे हैं।

बस्तर के दलपतसागर तालाब को कंक्रीट का जंगल बनने से बचाने को पूरा समाज लामबंद हो गया है। झारखण्ड से लेकर मालवा तक ऐसे ही उदाहरण सामने आ रहे है। उ.प्र. के बुंदेलखंड के सभी जिलों में राज्य सरकार ने छोटे किसानों के खेतों में तालाब बनाने की शुरुआत कर दी है जिसके तहत महोबा जिले में 500 और शेष जिलों– झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, जालौन और बांदा में ढाई–ढाई सौ तालाबों की खुदाई का काम किसानों ने भरी धूप में पूरा कर दिया है। यदि इसमें पानी भर जाता है तो एक एकड़ के खेत में हर तालाब दो बार तराई कर सकेगा।

**जल-संकट से जूझ रहे समाज ने नदी को तालाब से जोड़ने, गहरे कुओं से तालाब भरने, पहाड़ पर नालियां बनाकर उसका पानी तालाब में जुटाने, उपेक्षित पड़ी झिरिया का पानी तालाब में एकत्र करने जैसे अनगिनत प्रयोग किये हैं ।**

आमतौर पर हमारी सरकारें बजट का रोना रोती हैं कि पारंपरिक जल संसाधनों की सफाई के लिये बजट का टोटा है। हकीकत में तालाबों की सफाई और गहरीकरण अधिक खर्चीला काम नहीं है, ना ही इसके लिये भारी–भरकम मशीनों की जरूरत होती है। यह सर्वविदित है कि तालाबों में भरी गाद, सालों साल से सड़ रही पत्तियों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण ही उपजी है, जो उम्दा दर्जे की खाद है।

रासायनिक खादों ने किस कदर जमीन को चौपट किया है? यह किसान जान चुके हैं और उनका रुख अब कम्पोस्ट व अन्य देशी खादों की ओर है। किसानों को यदि इस खादरूपी कीचड़ की खुदाई का जिम्मा सौंपा जाये तो वे सहर्ष राजी हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में 'खेतों में पालिश करने' के नाम से यह प्रयोग अत्यधिक सफल व लोकप्रिय रहा है।

कर्नाटक में समाज के सहयोग से ऐसे कोई 50 तालाबों का कायाकल्प हुआ है, जिसमें गाद की ढुलाई मुफ्त हुई, यानी ढुलाई करने वाले ने इस बेशकीमती खाद को बेचकर पैसा कमाया। इससे एक तो उनके खेतों को उर्वरक मिलता है, साथ–ही–साथ तालाबों के रखरखाव से उनकी सिंचाई सुविधा भी बढ़ती है। सिर्फ आपसी तालमेल, समझदारी और अपनी परम्परा तालाबों के संरक्षण की दिली भावना हो तो, न तो तालाबों में गाद बचेगी न ही सरकारी अमलों में घूसखोरी की कीच होगी।

जल–संकट से जूझ रहे समाज ने नदी को तालाब से जोड़ने, गहरे कुओं से तालाब भरने, पहाड़ पर नालियाँ बनाकर उसका पानी तालाब में जुटाने, उपेक्षित पड़ी झिरिया का पानी तालाब में एकत्र करने जैसे अनगिनत प्रयोग किये हैं और प्रकृति के कोप पर विजय पाई है।

यह जरूरी है कि लोग सरकार पर निर्भरता छोड़कर घर से निकलें, तपती गर्मी में अपने मुहल्ले–कस्बों के पारम्परिक जल संसाधनों– तालाब, बावड़ी, कुओं आदि से गाद निकालने, गहरीकरण व मरम्मत का काम करें। यह गाद जिन खेतों में पहुंचेगी, वह सोना उगलेंगे ही। बस एक बात ख्याल करना होगा कि पारम्परिक जलस्रोतों के गहरीकरण में भारी मशीनों के इस्तेमाल से परहेज ही करें।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंधियारा तालाब की कहानी गौर करें– कोई दो दशक पहले वहाँ सूखा राहत के तहत तालाब गहराई का काम लगाया गया। इंजीनियर साहब ने तालाब के बीचों–बीच खूब गहरी खुदाई करवा दी। जब इंद्र देवता मेहरबान हुए तो तालाब एक रात में लबालब हो गया, लेकिन यह क्या? अगली सुबह ही उसकी तली दिख रही थी। असल में हुआ चूंकि बगैर सोचे हुई–समझे की गई खुदाई में तालाब की वह झिर टूट गई, जिसका संबंध सीधे इलाके के ग्रेनाईट भू संरचना से था। पानी आया और झिर से बह गया।

यहां जानना जरूरी है कि अभी एक सदी पहले तक बुंदेलखंड के इन तालाबों की देखभाल का काम पारंपरिक रूप से ढीमर समाज के लोग करते थे। वे तालाब को साफ रखते, उसकी नहर, बांध, जल आवक को सहेजते– एवज में तालाब की मछली, सिंघाड़े और समाज से मिलने वाली दक्षिणा पर उनका हक होता।

इसी तरह प्रत्येक इलाके में तालाबों को सहेजने का जिम्मा समाज के एक वर्ग ने उठा रखा था और उसकी रोजी–रोटी की व्यवस्था वही समाज करता था, जो तालाब के जल का इस्तेमाल करता था। तालाब तो लोक की संस्कृति, सभ्यता का अभिन्न अंग हैं और इन्हें सरकारी बाबुओं के लाल बस्ते के बदौलत नहीं छोड़ा जा सकता।

अभी बादल बरसने में कम–से–कम साठ दिन बाकी है, यदि समाज सप्ताह में केवल एक दिन अपने पुरखों की देन जल संसाधनों की सफाई के लिये घर से बाहर निकले और उनमें गन्दा पानी जाने से रोकने के प्रयास करे तो जान लें कि आने वाले दिन 'पानीदार' होंगे। ❑❑

# २२ अप्रैल कैसे बना पृथ्वी दिवस?

**भारतीय कालगणना** दुनिया में सबसे पुरानी है। इसके अनुसार, भारतीय नववर्ष का पहला दिन, सृष्टि रचना की शुरुआत का दिन है। आई.आई.टी., बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. बिशन किशोर कहते हैं कि यह एक तरह से पृथ्वी का जन्मदिन की तिथि है। तद्नुसार इस भारतीय नववर्ष पर अपनी पृथ्वी 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49 हजार 104 वर्ष की हो गई। वैदिक मानव सृष्टि सम्वत् के अनुसार मानव उत्पत्ति इसके कुछ काल बाद यानी अब से 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 115 वर्ष पूर्व हुई। जाहिर है कि 22 अप्रैल पृथ्वी का जन्म दिवस नहीं है। चार युग जब हजार बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस एक दिन के शुरु में सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है और संध्या होते–होते प्रलय। ब्रह्मा जी की आयु सौ साल होने पर महाप्रलय होने की बात कही गई है। रचना और प्रलय, यह सब हमारे अंग्रेजी कैलेण्डर के एक दिन में संभव नहीं है। स्पष्ट है कि 22 अप्रैल पृथ्वी का प्रलय या महाप्रलय दिवस भी नहीं है। फिर भी दुनिया इसे 'इंटरनेशनल मदर अर्थ डे' यानी 'अंतर्राष्ट्रीय मां पृथ्वी का दिन' के रूप में मनाती है। हम भी मनाते है, मगर यह तो जानना ही चाहिए कि क्या हैं इसके संदर्भ और मंतव्य?

## एक विचार

सच है कि 22 अप्रैल का पृथ्वी से सीधे–सीधे कोई लेना–देना नहीं है। जब पृथ्वी दिवस का विचार सामने आया, तो भी पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। वियतनामी युद्ध विरोध में उठ खडे हुए विद्यार्थियों का संघर्ष! 1969 में सांता बारबरा (कैलिफोर्निया) में बडे पैमाने पर बिखरे तेल से आक्रोशित विद्यार्थियों को देखकर गेलॉर्ड नेलसन के दिमाग में ख्याल आया कि यदि इस आक्रोश को पर्यावरणीय सरोकारों की तरफ मोड दिया जाये, तो कैसा हो। नेलसन, विसकोंसिन से अमेरिकी सीनेटर थे। उन्होंने इसे

*22 अप्रैल पथ्वी का प्रलय या महाप्रलय दिवस भी नहीं है। फिर भी दुनिया इसे 'इंटरनेशनल मदर अर्थ डे' यानी 'अंतर्राष्ट्रीय मां पथ्वी का दिन' के रूप में मनाती है। हम भी मनाते है, मगर यह तो जानना ही चाहिए कि क्या हैं इसके संदर्भ और मंतव्य?*

**– अरूण तिवारी**

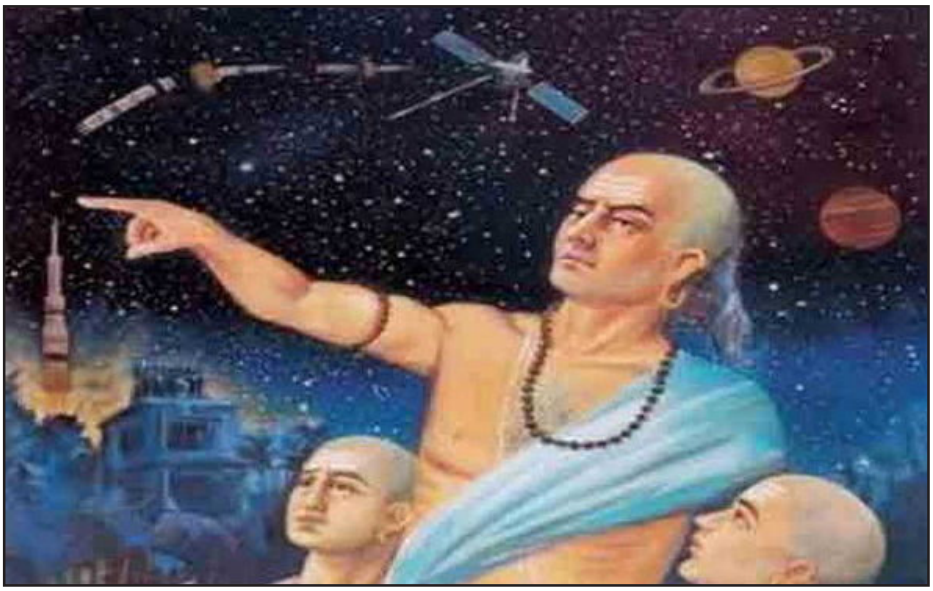

देश को पर्यावरण हेतु शिक्षित करने के मौके के रूप में लिया। उन्होंने इस विचार को मीडिया के सामने रखा। अमेरिकी कांग्रेस के पीटर मेकेडलस्की ने उनके साथ कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की। डेनिस हैयस को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया।

### आवश्यकता बनी विचार की जननी

खंगाला तो पता चला कि साठ का दशक, हिप्पी संस्कृति का ऐसा दशक था, जब अमेरिका में औद्योगीकरण के दुष्प्भाव दिखने शुरु हो गये थे। आज के भारतीय उद्योगपतियों की तरह उस वक्त अमेरिकी उद्योगपतियों को भी कानून का डर, बस! मामूली ही था। यह एक ऐसा दौर भी था कि जब अमेरिकी लोगों ने औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से उठते गंदे धुंए को समृद्धियों के निशान के तौर पर मंजूर कर लिया था। इसी समय इस निशान और इसके कारण सेहत व पर्यावरण पर पड रहे असर के खिलाफ जन जागरूता की दृष्टि से रचित मिस रचेल कार्सन की लिखी एक पुस्तक की सबसे अधिक बिक्री ने साबित कर दिया था कि पर्यावरण को लेकर जिज्ञासा भी जोर मारने लगी है।

### विचार को मिला दो करोड अमेरिकियों का साथ

गेलॉर्ड नेलसन की युक्ति का नतीजा यह हुआ कि 22 अप्रैल, 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सडकों, पार्कों, चौराहों, कॉलेजों, दफ्तरों पर स्वस्थ–सतत् पर्यावरण को लेकर रैली, प्रदर्शन, प्रदर्शनी, यात्रा आदि आयोजित किए। विश्वविद्यालयों में पर्यावरण में गिरावट को लेकर बहस चली। ताप विद्युत संयंत्र, प्रदूषण फैलाने वाली ईकाईयां, जहरीला कचरा, कीटनाशकों के अति प्रयोग तथा वन्य जीव व जैवविविधता सुनिश्चित करने वाली अनेकानेक प्रजातियों के खात्मे के

**नगरों पर गहराते संकट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मां पृथ्वी का यह दिन 'क्लीन-ग्रीन सिटी' के नारे तक जा पहुंचा है।**

खिलाफ एकमत हुए दो करोड अमेरीकियों की आवाज ने इस तारीख को पृथ्वी के अस्तित्व के लिए अहम बना दिया। तब से लेकर आज तक यह दिन दुनिया के तमाम देशों के लिए खास ही बना हुआ है।

### आगे बढता सफर

पृथ्वी दिवस का विचार देने वाले गेलॉर्ड नेलसन ने एक बयान में कहा – ''यह एक जुआ था, जो काम कर गया।'' सचमुच ऐसा ही है। आज दुनिया के करीब 184 देशों के हजारों अंतर्राष्ट्रीय समूह इस दिवस के संदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वर्ष 1970 के प्रथम पृथ्वी दिवस आयोजन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के दिल में भी ख्याल आया कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक एजेंसी बनाई जाये। वर्ष 1990 में इस दिवस को लेकर एक बार उपयोग में लाई जा चुकी वस्तु के पुर्नोपयोग का ख्याल व्यवहार में उतारने का काम विश्वव्यापी संदेश का हिस्सा बना। 1992 में रियो डी जिनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन ने पूरी दुनिया की सरकारों और स्वयंसेवी जगत में नई चेतना व कार्यक्रमों को जन्म दिया। एक विचार के इस विस्तार को देखते हुए गेलॉर्ड नेलसन को वर्ष 1995 में अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान 'प्रेसिडेन्सियल मैडल ऑफ फ्रीडम' से नवाजा गया। नगरों पर गहराते संकट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मां पृथ्वी का यह दिन 'क्लीन–ग्रीन सिटी' के नारे तक जा पहुंचा है।

### मंतव्य

अंतर्राष्ट्रीय मां पृथ्वी के एक दिन 22 अप्रैल के इस सफरनामे को जानने के बाद शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि पृथ्वी दिवस कैसे अस्तित्व में आया और इसका मूल मंतव्य क्या है। आज, जब वर्ष 1970 की तुलना में पृथ्वी हितैषी सरोकारों पर संकट ज्यादा गहरा गये हैं कहना न होगा कि इस दिन का महत्व कम होने की बजाय बढ़ा ही है। इस दिवस के नामकरण में जुडे संबोधन 'अंतर्राष्ट्रीय मां' ने इस दिन को पर्यावरण की वैज्ञानिक चिंताओं से आगे बढ़कर वसुधैव कुटुम्बकम की भारतीय संस्कृति से आलोकित और प्रेरित होने का विषय बना दिया है। 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मां के बहाने खुद के अस्तित्व के लिए चेतने और चेताने का दिन है। आइये, चेतें और दूसरों को भी चेतायें।❑❑

# युग पुरुष महाराणा प्रताप

**'माई एहड़ा पूत जण, जेहड़ा राणा प्रताप'**
**अकबर सूतो औझके, जाण सिराणे सांप।'**

सर्वस्व त्यागकर अपने पवित्र आदर्शों के लिए अपने जीव तक की आहूति देने वालों को किसी भी प्रकार क्षय नहीं होता, मृत्यु भी उन्हें अमरत्व प्रदान करती है, तब इन वीरात्माओं का मानवीय हृदय पर अखंड शासन स्थापित हो जाता है। उनकी कीर्ति की वह अमरबेल निरंतर फैलती है और फूलती रहती है। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप ऐसे ही एक महान् व्यक्ति हुए हैं, जिनका स्मरण करते ही हमारे समक्ष एक महान् राष्ट्र भक्त, त्यागी, तपस्वी एवं जीवट व्यक्तित्व के धनी का चित्र उपस्थित हो जाता है। युद्ध नायक, डील–डौल से, लंबे आकृति से वैभवपूर्ण, ललाट उच्च, मूंछे भरी हुई और आंखों से तेजस्वी दृष्टिगोचर होता था। कष्टों ने उन्हें धैर्य, शांति, साहस और निष्ठा का पाठ पढ़ाया था।

## प्रारंभिक जीवन

महाराणा प्रताप का जन्म 13 जून, 1540 ई. को कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदयसिंह की रानी जैवतीबाई की कोख से हुआ। जन्म से ही प्रताप ने संकटों का सामना किया। प्रताप का प्रारंभिक जीवन अरावली की पहाड़ियों में स्थित दुर्गों में बीता। प्रसिद्ध इतिहासकार डा. गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 'जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों में भटकते हुए उनके प्रारंभिक जीवन चरित्र का निर्माण हुआ।' इस कारण उनमें सहज की अपने देश के प्रति श्रद्धा और विश्वास जाग्रत हो गया था। जिस वातारण में उनका बाल्यकाल बीता था, उसने उनमें एक दृढ़ चरित्रबल व जीव का वह दर्शन उत्पन्न कर दिया था जो उस समय के अन्य राजपूतों की अपेक्षा उनकी विशिष्टता दिखाता है।

*इस संसार में जैसा राणा हुआ है वैसा न तो कभी कोई दूसरा हुआ और न कभी होगा। राणा प्रताप युधिष्ठिर के समान सत्यावक्ता, दधीचि के समान उदार बुद्धि, भीष्म के समान दढ़ प्रतिज्ञ, भीम के समान युद्ध करने वाला तथा राम के समान प्रजापालक था। वह वास्तव में मुज्जराज कहे जाने योग्य थे।*
**– डॉ. विजय वशिष्ठ**

## राज्याभिषेक

राणा उदयसिंह के देहांत के पश्चात् 28 फरवरी 1572 के दिन जब महाराणा प्रताप को राजगद्दी प्राप्त हुई तब मेवाड़ में ही नहीं, संपूर्ण भारत के राजनैतिक इतिहास में एक सर्वथा अनोखे काल का प्रारंभ हुआ। जिससे स्वाधीनता के सजग प्रहरी राणा प्रताप ने वह अखंड ज्योति जलाई, जो अनेक शताब्दियों के बीत जाने पर भी स्वाधीनता के अनन्य साधकों और देश पर बलिदान होने वालों को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी।

प्रताप सिंह अपना प्रताप स्वयं फैलाने वाला था। इतिहासकार लिखते है ''इस संसार में जैसा राणा हुआ है वैसा न तो कभी कोई दूसरा हुआ और न कभी होगा। राणा प्रताप युधिष्ठिर के समान सत्यावक्ता, दधीचि के समान उदार बुद्धि, भीष्म के समान दृढ़ प्रतिज्ञ, भीम के समान युद्ध करने वाला तथा राम के समान प्रजापालक था। वह वास्तव में मुज्जराज कहे जाने योग्य थे।''

राणा प्रताप ने अपने जीवन में अनेक कष्ठ सहे, परंतु स्वाभिमान एवं राष्ट्र भक्ति को नहीं त्यागा। गोपीनाथ शर्मा ने ग्लोरी ऑफ मेवाड़ में लिखा है कि ''वह (महाराणा प्रताप) घूमते रहने वाला जीवन जी रहा था, अपने परिवार का पालन घास खिलाकर कर रहा था,

रातें उसकी चटाई पर बेचैनी से बीतती थी।'' जनजागरण तथा जनसंगठन की क्षमता भी महाराणा प्रताप में खूब थी। संपूर्ण पहाड़ी भागों में घूम–घूमकर तथा कष्टसाध्य जीवन बिताकर उन्होंने जनता के नैतिक स्तर को बनाये रखा। प्रताप ने उनके जीवन की समस्या को अपने जीवन की समस्या बनाया। वे कई दिनों तक ग्रामीण जनता के बीच घूमते रहे और जन आंदोलन द्वारा देश को सजग बनाये रखा। भील उनके सहयोगी एवं सच्चे मित्र बन गये। राणा प्रताप ने उनके गुणों का युद्ध में उपयोग किया।

महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन करते हुए अबुल फजल ने 'अकबरनामा' में लिखा है कि ''अपने असीम साहस, आलौकिक शौर्य, दृढ़ चरित्र, अपूर्व सैनिक प्रतिभा, अनूठी देश–भक्ति, स्वतंत्रता प्रेम, अजेय धैर्य, रचनात्मक योग्यता, राजनैतिक अंतर्दृष्टि तथा दूरदर्शिता एवं कष्टपूर्ण संघर्षमय जीवन के कारण राणा प्रताप चिरस्मरणीय ही नहीं, अपितु पराजित होने पर भी विजेता मुगल सम्राट से महान हैं।'' महाराणा प्रताप के जीवन के संबंध में डा. गोपीनाथ की मान्यता है कि ''उनके वनवासी जीवन की कहानी उनके सच्चे जीवन की कहानी है। इस कहानी से उनके सच्चे देश–प्रेम, राजकौशल, वीरता, सहिष्णुता और जीविता के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यदि हम प्रताप के महत्व को समझना चाहते हैं तो हमें उन पहाड़ों के संदर्भ में उनका अध्ययन करना चाहिए जहां वर्षों रहकर प्रताप ने मुगलों का मुकाबला किया और देश में सुव्यवस्था स्थापित की।''

## हल्दीघाटी का युद्ध

इतिहास प्रसिद्ध यह युद्ध 18 जून, 1576 को प्रातःकाल हल्दीघाटी और खेमनोर गांव के बीच विस्तृत मैदान में हुआ। यह युद्ध शाही सेना और महाराणा प्रताप के सैनिक वीरों के मध्य हुआ। राजस्थान के गौरव और स्वाधीनता के इस अद्वितीय योद्धा प्रताप की याद दिलाने वाला वह युद्ध स्वदेश के लिए मर मिटने वाले उन स्वामिभक्त राष्ट्रप्रेमी वीरों के पुनीत रूधिर से सींचा जाकर राजस्थान की थर्मोपोली और समूचे भारत के स्वाधीनता प्रेमी के लिए एक विशिष्ट पूज्य मुख्य क्षेत्र बन गया। कर्नल टॉड ने प्रथम बार कहा कि ''हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है और दिवेर की रणभूमि उसकी मैराथन है।''

एक ओर 80 हजार की मुगल सेना हल्की तोपों के साथ मानसिंह के नेतृत्व में पहुंच गयी, तो दूसरी ओर 22 हजार सैनिक केवल तीर कमान के सहारे किंतु आत्मबल और वज्र हृदय

**महाराणा जब सिहासनारूढ़ हुए तब उनके समक्ष दो प्रमुख समस्याएं थी–प्रथम, राज्य की समुचित व्यवस्था तथा द्वितीय अकबर की बढ़ती हुई शक्ति एवं सत्तावादी नीतियों का मुकाबला करना।**

लेकर स्वतंत्रता को बचाने के लिए मारने–मरने के लिए महाराणा प्रताप के नेतृत्व में आगे बढ़े। 18 जून, 1576 के दिन प्रातः 9 बजे युद्ध शुरू हुआ, पहले की प्रहार में मानसिंह की सेना के पांव उखड़ गये और भगदड़ मच गई। 5–6 मील तक बनास पार कर सेना भागती ही रही, उसी समय हल्ला मचा कि बादशाह स्वयं आ पहुंचे हैं, इससे शाही सेना में पुनः हिम्मत आ गयी और भागती सेना के पैर पुनः रणभूमि में टिक गये। जमकर युद्ध हुआ। अबुल फजल ने लिखा है कि ''दोनों पक्षों के वीरों ने लड़ाई में जान सस्ती और इज्जत महंगी कर दी।''

महाराणा चारों ओर से शत्रु सेना से घिर गये। महाराणा को बचाने के लिए झालामान आगे बढ़े, उन्होंने राजमुकुट स्वयं धारण कर लिया तथा घोड़े की लगाम पकड़कर महाराणा प्रताप को रणभूमि से विलग किया। झाला प्रताप ने प्रोणोत्सर्ग कर स्वाभिभक्ति का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस युद्ध से प्रताप की धाक मुगल सेना पर जम गई और मेवाड़ी सेना का भय मुगलों के दिल में बैठ गया। भय के कारण उन्होंने महाराणा का पीछा तक नहीं किया। इस युद्ध में प्रताप का पलड़ा भारी रहा। अकबर ने आसफ खां व मानसिंह का कुछ समय तक दरबार में प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया था, क्योंकि वे प्रताप को जीतने की आकांक्षा को पूरा करने में सफल नहीं रहे थे।

हल्दी घाटी स्वतंत्रता संग्राम का अनुष्ठान एक ऐसे दीपक के समान है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने रक्त रूपी तेल से प्रताप कीर्ति की अखण्ड ज्योति प्रज्ज्वलित की, जिसकी प्रकाशमान किरणें स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने और स्वतंत्र रहने की प्रेरणा मानव जाति को अनन्त काल तक देती रहेगी।

## शासन व्यवस्था

महाराणा प्रताप न केवल कुशल योद्धा तथा योग्य सेनापित थे वरन् एक कुशल शासक भी थे, वे यद्यपि एक छोटे से राज्य के स्वामी थे, किन्तु उनमें नेतृत्व तथा कुशल शासक के सारे गुण विद्यमान थे। महाराणा प्रताप जब सिहासनारूढ़ हुए तब उनके समक्ष दो प्रमुख समस्याएं थी–प्रथमतः राज्य की समुचित व्यवस्था तथा द्वितीय अकबर की बढ़ती हुई शक्ति एवं सत्तावादी नीतियों का मुकाबला करना। प्रथम समस्या के समाधान के लिए प्रताप ने बड़ी चतुराई, कौशल तथा दृढ़ता के साथ मेवाड़ की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को सामरिक आधार पर रखा। सुरक्षा की दृष्टि से अकबर मेवाड़ को अकेला कर घेरने में तो सफल हुआ, लेकिन प्रबल शक्ति महाराणा प्रताप को पराजित करने और झुकाने में सफल नहीं हुई।

प्रतापकालीन मेवाड़ की शासन व्यवस्था का सिलसिलेवार प्रमाणिक विवरण प्राप्त नहीं होता। उन्होंने अपने स्थानीय जीवन का प्रारंभ चांवड़ को मेवाड़ की राजधानी स्थापित कर प्रारंभ किया। चांवड़ में प्रताव को मुगल आक्रमणों से विश्राम तो मिला ही साथ ही उस समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया गया। शासन प्रबंध का विभागीय वर्गीकरण किया गया और उन पर अलग–अलग अधिकारी नियुक्त किये गये। भू–प्रबंध व्यस्थित किया गया।

युद्धकाल में भी कृषि तथा वाणिज्य की कुशल व्यवस्था द्वारा सैनिक तथा सामान्य नागरिकों को दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती रही। जगह–जगह पहाड़ी स्थलों में खेती व्यवस्थाओं से जनता के लिए काम खोज निकाला गया। कृषि की उन्नति की तरफ ध्यान दिया गया और व्यापार तथा वाणिज्य पुनः सामान्य स्थिति में आ गये। मालवा और गुजरात के मार्ग खुल गये। आवागमन सरल हो गया।

प्रताप की राजधानी में न्याय का समुचित प्रबंध था, उचित दंड के फलस्वरूप समाज में अराजकता नहीं थी। सभी में नैतिक आचरण था। आज्ञा की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिये जाने में विलंब नहीं किया जाता था। महाराणा प्रताप की स्थापत्य कला में काफी रूचित थी। डा. गोपीनाथ ने 'मेवाड़ मुगल संबंध' नामक पुस्तक में लिखा 'मेवाड़ की निर्माण शैली ने महलों की स्थापत्य कला में युद्ध की भीषणता को बनाये रखा। हर स्थान में बचाव, रक्षा, सुदृढ़ता आदि बातों को ध्यान में रखा गया। संपूर्ण राज प्रासाद के स्वरूप में हमें प्रताप के कठोर जीवन की झांकी देखने को मिलती है।' राणा प्रताप ने साहित्य तथा संस्कृति की अभिवृद्धि को काफी प्रोत्साहन दिया। मेवाड़ की शैली का भारतीय चित्रकला में प्रमुख स्थान है।

## धार्मिक सहिष्णुता

विषम संकटकाल में भी महाराणा प्रताप ने अपनी उदारता और मानव धर्म को कभी नहीं भुलाया। प्रताप ने किसी व्यक्ति की धर्म के नाम पर कभी बलि ली हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। राज्यादेश का उल्लंघन करने के लिए एक हिन्दू किसान को मृत्युदंड अवश्य दिया था। जाहिर है कि प्रताप में धार्मिक उत्तेजना अथवा बदला लेने की भावना नहीं थी। हल्दीघाटी के युद्ध में राजा मानसिंह कछवाह मुगल सेनापति था, तो प्रताप की हराबल में हकीम खां सूर था। प्रताप के शासन में सभी को समान रूप से योग्यतानुसार राज्याश्रय प्राप्त होता था। उनकी नीतियों में संकीर्णता, सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं था। अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में उल्लेख किया है कि जब युद्ध समय में कुवर अमर सिंह मिर्जा खां की स्त्रियों को अपने पड़ाव में ले आया था तब प्रताप ने शीघ्रता से ही उन्हें सकुशल मिर्जा खां के पास पहुंचा दिया। तब ही रहीम खानखाना ने उसे लिख भेजा–

*'धरम रहसी–धरा, खप जासी खुरसाण।*
*अमर बिसंबर ऊपरे, राख नहव्यों राण।।'*

यह कार्य राणा की शत्रु के प्रति उदारता, सहिष्णुता और नारीत्व के प्रति सम्मान और पवित्रता का द्योतक है।

**प्रताप के शासन में सभी को समान रूप से योग्यतानुसार राज्याश्रय प्राप्त होता था। उनकी नीतियों में संकीर्णता, सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं था।**

## महाप्रयाण

57 वर्ष की उम्र में 25 वर्ष तक राज्य करने वाले तथा मुगल सत्ता के समक्ष ने झुकने वाले महाराणा प्रताप को 19 जनवरी, 1597 को मेवाड़ की राजधानी चांवड़ में स्वर्गवास हो गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के एक सुनहरे युग की समाप्ति हो गई। जब प्रताप की मृत्यु का समाचार लाहौर में अकबर के पास पहुंचा तो वह स्तब्ध और उदास हो गया। उनका यह हाल देखकर शाही दरबारी ने एक पद के माध्यम से कहा 'हे प्रताप सिंह तेरी मृत्यु पर शाह (अकबर) ने दांतों के बीच जीभ दबाई, निःश्वासें छोड़ी और उसकी आंखों में भी आंसू भर आये। गहलोत राणा (प्रताप) तेरी ही विजय हुई।'

महाराणा प्रताप की महत्ता उस युग में ही नहीं, वरन् आधुनिक युग में भी कम नहीं हुई। जब स्वाधीनता संघर्ष के परिणामस्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके लिए महाराणा प्रताप एक प्रेरणा पुंज रहे। स्वाधीन भारत में महाराणा प्रताप का महत्व और गौरव किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ। महाराणा प्रताप के जीवन से ही यह प्रेरणा मिलती है कि आक्रमणकारी एवं आततायी का सामना बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी किया जाए।

महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक अंगारा था, जो आत्म–सम्मान और देश–गौरव की रक्षार्य रात–दिन जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी संपूर्ण भारत में ऐसा आलोक भर दिया, जिसकी प्रखर किरणों ने भारत–माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी का शंखनाद किया। आज राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता और अधिक है। अब समय आ गया है, जब हम अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप को महान कहें। युवकों में देश–प्रेम की भावना जागृत करें तथ इस देश में एकता एवं अखण्डता को कायम रखें।

महाराणा प्रताप को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं एवं भाव जागृत करें कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। ❑❑

# आयुर्वेदः जल ही जीवन है

**जल** ही जीवन है। बिना जल के जीवन की कल्पना करना संभव नहीं। पृथ्वी के दो तिहाई हिस्से पर पानी और एक तिहाई हिस्सा पर जीवन है। आज मनुष्य पानी की खोज में चांद से लेकर मंगल तक को खंगाल चुका है, ताकि वहां जीवन की संभावनायें तलाशी जा सके। लेकिन, क्या धरती पर रहने वाले हम पानी के वास्तविक मूल्य को समझते हैं। अधिकतर माना जाता है कि पानी तो जितना पियो उतना कम है, लेकिन, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। हर चीज की अति बुरी होती है और पानी भी कोई अपवाद नहीं। शरीर से पसीने, मलमूत्र और सांसों आदि के माध्यम से जितना पानी निकालते हैं उससे ज्यादा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। पानी का ओवरडोज किडनी पर आवश्यकता से अधिक दबाव डालता है। आपकी गतिविधियां आपकी पानी पीने की क्षमता को निर्धारित करती हैं। प्रति 100 कैलोरी सेवन पर आपको आधा गिलास या 100 मिली पानी पीना चाहिए। इसी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप ज्यादा भाग–दौड़/कठोर परिश्रम करते हैं, तो उसमें 500 से 1000 तक कैलोरी जुड़ जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो ऐसे में आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए।

महिलाओं और पुरूषों के पानी पीने की आवश्यकता उनके बीएमआर (चयापचयी दर जो आधारिक दशाओं में मापी जाती है, जैसे खाना खाने के 12 घंटे एवं आराम के साथ पूरी नींद लेने के पश्चात् मापी जाती है) और एक्टिविटी लेवल पर निर्भर करती है। साधारणतयाः जिम न जाने वाले व्यक्ति को 500 कैलोरी और जिम जाने वाले को 1000 कैलोरी के हिसाब से पानी पीना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन भर में 12–13 गिलास पानी पीना पर्याप्त होता है।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पानी का विशेष महत्व है। पानी को सही मात्रा एवं

*शरीर से पसीने, मलमूत्र और सांसों आदि के माध्यम से जितना पानी निकालते हैं उससे ज्यादा पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। पानी का ओवरडोज किडनी पर आवश्यकता से अधिक दबाव डालता है। आपकी गतिविधियां आपकी पानी पीने की क्षमता को निर्धारित करती हैं।*
**– स्वदेशी संवाद**

समयानुसार लेना, कई रोगों को दूर भगाता है। व्यस्क पुरूष मानव शरीर में पानी की मात्रा 60 प्रतिशत, व्यस्क स्त्री शरीर में 65 प्रतिशत तथा नवजात शिशु में 73 प्रतिशत होता है। पानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा की तरह ही पोषण का काम करता है। पानी हमारे घुटनों, कलाई और सभी अंतरंग भागों की चिकनाई के साथ–साथ जोड़ों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं पानी हमारी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है साथ ही हमें कई सारी बिमारियों से भी दूर रखता है। कई सारी रोजमर्रा की छोटी–छोटी बिमारियों का इलाज हम पानी पीके से कर सकते हैं।

### पानी पीने के आयुर्वेद तरीके/समय

1. पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए (जैसे भोजन करने के लिए बैठते है।)
2. घूंट–घूंट/रूक–रूककर पानी पीना चाहिए (एकदम नहीं।)
3. पानी ताजा एवं स्वच्छ हो। थोड़ा गर्म हो तो ज्यादा अच्छा। (फ्रीज का पानी नहीं।)
4. भोजन से आधा घंटा और भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीना लाभप्रद होता है।
5. सुबह उठकर पेट भर पानी पीना चाहिए।
6. सोने से पहले कम से कम एक गिलास पानी पीने से नींद अच्छी आती है।
7. चाय पीने से पहले आधा या एक गिलास पानी पीने से चाय का दोष समाप्त होता है।
8. दिन में कम से कम 10–12 गिलास पानी पीना चाहिए।

### तांबे के बर्तन में पानी पीने का लाभ

आयुर्वेद में कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिलते है, इस पानी से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते है। तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी में शरीर के तीनों दोषों (वात, पित्त एवं कफ) को संतुलित करने की क्षमता होती है। तांबे के बर्तन में संग्रहित पानी को ताम्र जल के नाम से जाना जाता है। तांबे के लोटे, जग या ग्लास में कम से कम 8 घंटे तक रखा हुआ पानी ही लाभकारी होता है। तांबे के बर्तन में रखे हुए जल के स्वास्थ्य लाभ निम्न प्रकार हैं–

**बैक्टीरिया समाप्त**–कॉपर को प्रकृति में ऑलीगोडायनेमिक के रूप में (बैक्टीरिया पर धातुओं की स्टरलाइज प्रभाव) जाना जाता है और इसमें रखे पानी के सेवन से बैक्टीरिया को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसमें रखे पानी को पीने से डायरिया, दस्त और पीलिया जैसे रोगों के कीटाणु भी मर जाते है। लेकिन पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिये।

**तांबे के लोटे, जग या ग्लास में कम से कम 8 घंटे तक रखा हुआ पानी ही लाभकारी होता है।**

**थॉयरायड ग्रंथि नियंत्रित**–कॉपर की धातु के स्पर्श वाला पानी शरीर में थॉयरायड ग्रंथि को नॉर्मल कर देता है और उसकी कार्यप्रणाली को भी नियंत्रित करता है।

**त्वचा स्वस्थ**–सुबह–सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीने से त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है।

**गठिया और जोड़ों की सूजन**–जोड़ों में दर्द और गठिया की शिकायत होने पर तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीने से लाभ मिलता है। पानी में ऐसे गुण आ जाते है जिससे बॉडी में यूरिक एसिड कम हो जाता है और गठिया की समस्या भी दूर हो जाती है।

**दीर्घ युवावस्था**–तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से झुर्रिया, त्वचा का ढीलापन आदि दूर हो जाता है।

**पाचन क्रिया दुरूस्त**–एसिडिटी/गैस/पेट की कोई अन्य साधारण समस्या होने पर तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीने से आराम मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर आप अपने शरीर से विषाक्त पदार्थो को बाहर निकालना चाहते है तो तांबे के बर्तन में कम से कम 8 घंटे रखा हुआ जल पिएं, इससे राहत मिलेगी और समस्याएं भी दूर होगी।

**खून बढ़ाना**– कॉपर शरीर की अधिकांश प्रक्रियाओं में बेहद आवश्यक होता है। यह शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से खून की कमी/विकार दूर होता है।

**वजन घटाना**– अगर वजन घटाना है तो उसे तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिये, इस पानी को पीने से बॉडी की अतिरिक्त वसा कम हो जाती है और शरीर में कोई कमी या कमजोरी भी नहीं आती है।

**दिल स्वस्थ**– यदि कोई दिल के रोग से ग्रसित है या उसे हार्ट की किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह तांबे के जग में रात को पानी रख दें और उसे सुबह उठकर पी लें। इससे उसे काफी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तांबे के बर्तन में रखे हुए जल को पीने से पूरे शरीर में रक्त का संचार बेहतरीन रहता है।

**कैंसर से लड़ने में सहायक**– कैंसर होने पर हमेशा तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल पीना चाहिये, इससे लाभ मिलता है क्योंकि तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल वात, पित्त और कफ की शिकायत को दूर करता है। इस प्रकार के जल में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो इस रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अमेरिकन कैंसर सोसायटी के अनुसार, कॉपर कई तरीके से कैंसर मरीज की हेल्प करती है, यह धातु लाभकारी होती है जिसमें रखा हुआ पानी सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करता है। यह एंटीकैंसर इफेक्ट प्रदान करता है।

**गर्म पानी के लाभ**

वैज्ञानिक मानते है कि गर्म पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर हो जाते हैं। सुबह खाली पेट व रात को खाने के बाद पानी पीने से पाचन संबंधी दिक्कते खत्म हो जाती है एवं कब्ज और गैस जैसी समस्याएं परेशान नहीं करती। मुख्यतः गर्म पानी पीने के निम्नलिखित फायदे होते है–

**मुँहासे और पिंपल्स**–मुँहासे और पिंपल्स की समस्या आम बात है। इससे बचने के लिए रोज सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पिए।

**गले और नाक के रक्त संकुलन (कन्जेस्चन) में आराम**– ठंड में अक्सर देखा गया है कि लोग गले की समस्या से परेशान रहते हैं। जिससे आगे चल कर खासी और खराश जैसी परेशानियाँ

**गर्म पानी पीने से सबसे ज्यादा फायदा हमारे पाचन तंत्र को मिलता है। गर्म पानी पीने से आंतों में जमा मल आसानी से निकल जाता है। जिससे आपका पेट साफ रहता है।**

का सामना करना पड़ता है। इससे बचने के लिए गर्म पानी पिए और गर्म पानी से ही गरारा भी करें।

**बालों के लिए फायदेमंद**–गर्म पानी बालों के लिए भी फायदेमंद है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है साथ ही नए बालों को भी उगने में मदद करता है।

**विषैले तत्वों को बाहर करे**–गर्म पानी पीने से शरीर से हर तरह के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे पसीना निकलता है और अगर आप उसी गर्म पानी में नींबू डाल लें तो वह और फायदा करेगा।

**रक्त संचार बढ़ता है**–अगर शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो आपको कई सारी बीमारियां घेर सकती हैं। इसे बचने के लिए गर्म पानी पियें यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कई सारे रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है।

**पेट साफ**–गर्म पानी पीने से सबसे ज्यादा फायदा हमारे पाचन तंत्र को मिलता है। गर्म पानी पीने से आंतों में जमा मल आसानी से निकल जाता है। जिससे आपका पेट साफ रहता है और कब्ज की परेशानी में भी आराम दिलाता है।

**वजन कम**–हम सब चाहते है कि हम फिट रहें लेकिन इसके लिए व्यायाम नहीं करना चाहते हैं तो रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी पिए। यह आपके शरीर से अनचाही वसा निकल देगा और आपको एक खूबसूरत शरीर मिलेगा।

**महिलाओं के लिए भी विशेष राहत**– महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अगर पेट दर्द हो तो ऐसे में एक गिलास गुनगुना पानी पीने से राहत मिलती है। दरअसल इस दौरान होने वाले पैन में मसल्स में जो खिंचाव होता है उसे गर्म पानी रिलैक्स कर देता है।

**उम्र घटाए**–विषैले पदार्थों का आपके शरीर से निकलना बहुत जरुरी है, क्योंकि यह आपको जल्दी बूढ़ा बनाता है। सुबह गर्म पानी पीने से आपकी त्वचा की झुर्रिया कम होती है तथा पेट भी साफ रहता है।

अतः हमारे जीवन में पानी अमृत समान है। अगर पानी को नियमित एवं संतुलित मात्रा में लिया जाए तो हम निरोगी एवं दीघार्यु रह सकते है तथा अपने धन को संचित कर सकते है।❑❑

## :: सूचना ::

**स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।**

**संपादक, स्वदेशी पत्रिका**

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो। हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–व्हाटसएप। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –

# लू लगने से मृत्यु क्यों होती है?

हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इस तापमान पर ही हमारे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर पाते है। पसीने के रूप में पानी बाहर निकालकर शरीर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान संतुलित रखता है। शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना बंद कर देता है। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री के पार हो जाता है और शरीर की कूलिंग व्यवस्था ठप्प हो जाती है। तब शरीर का तापमान 37 डिग्री से ऊपर पहुँचने लगता है। शरीर का तापमान जब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब रक्त गरम होने लगता है और रक्त में उपस्थित प्रोटीन पकने लगता है (जैसे उबलते पानी में अंडा पकता है)। स्नायु कड़क होने लगते है इस दौरान सांस लेने के लिए जरुरी स्नायु भी काम करना बंद कर देते है। शरीर का पानी कम हो जाने से रक्त गाढ़ा होने लगता है, ब्लडप्रेशर धीमा हो जाता है, महत्वपूर्ण अंग (विशेषतः ब्रेन) तक ब्लड प्रवाह रुक जाता है। व्यक्ति कोमा में चला जाता है और उसके शरीर के एक–एक अंग कुछ ही क्षणों में काम करना बंद कर देते है, और उसकी मृत्यु हो जाती है।

**बचाव**–लगातार थोडा–थोडा पानी पीते रहना चाहिए और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री किस तरह रह पायेगा इस ओर ध्यान देना चाहिए। लगातार पसीना निकलते वक्त भी पानी पीते रहना अत्यंत जरुरी और आवश्यक है। ❑

## गर्म एवं ठंडे स्वाद्य पदार्थ

| | | | |
|---|---|---|---|
| सेव | –ठंडा | इलायची | –ठंडा |
| चीकू | –ठंडा | पपीता | –उष्ण |
| संतरा | –उष्ण | अनानस | –उष्ण |
| नींबू | –उष्ण | अनार | –ठंडा |
| प्याज | –ठंडा | गन्ना | –उष्ण |
| आलू | –उष्ण | नमक | –ठंडा |
| पालक | –ठंडा | मूँग दाल | –ठंडा |
| टमाटर | –उष्ण | चना दाल | –उष्ण |
| करेला | –उष्ण | गुड़ | –उष्ण |
| गोभी | –ठंडा | तिल | –उष्ण |
| गाजर | –ठंडा | मूंगफली/बदाम | |
| मिर्ची | –उष्ण | काजू/अखरोट/ | |
| मक्का | –उष्ण | खजूर | –उष्ण |
| मैथी | –उष्ण | हल्दी | –उष्ण |
| बेंगन | –उष्ण | कॉफी | –ठंडा |
| भिंडी | –उष्ण | दूध/दही/ | |
| चुकंदर | –ठंडा | घी/छाछ/ | |
| सौंफ | –ठंडा | चावल | –ठंडा |

***गर्मी में ठंडे पदार्थ अधिक सेवन करने से होने वाली परेशनियों से बचा जा सकता है।*** – आयुर्वेद

# गन्ने का जूश बनाम कोल्ड ड्रिंक

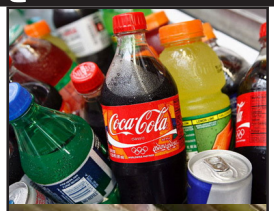

**कोल्ड ड्रिंकः** मैं बड़ी–बड़ी डिग्री धारक/पढ़े–लिखे लोगों की पहली और आखिरी पसंद हूं और तुम..?

**गन्ने का जूशः** मैं कम पढ़े लिखे लोगों की पसंद हूँ।

**कोल्ड ड्रिंकः** मेरे अंदर फास्फोरिक एसिड है और तुम्हारे अंदर ..?

**जूशः** मेरे अंदर आयरन है।

**कोल्ड्रिंकः** मेरे अंदर कैफीन है।

**जूशः** मेरे अंदर कैल्शिम है।

**कोल्ड्रिंकः** सोडियम ग्लूटामेट है।

**जूशः** मेरे अंदर गलूकोज है।

**कोल्ड्रिंकः** मेरे अंदर $Co_2$ है।

**जूशः** मेरे अंदर प्राणवायु रूपी आक्सीजन ($O_2$) है।

**कोल्ड्रिंकः** कैफीन, आर्सेनिक, कैडमियम, पोटैसियम सोरबेट, मिथाइलबेन्जीन, एस्पर्टेम है।

**जूशः** प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस और जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिसन्स है जो मानव शरीर के लिए उपयोगी है।

**कोल्ड्रिंकः** मुझे अधिकतर विदेशी कंपनियां बनाती है और करोड़ों रुपया भारत से लूट कर विदेश ले जाती है।

**जूशः** मैं किसान के परिश्रम और स्नेह से पैदा होकर अमृत बन जाता हूं।

**कोल्ड्रिंकः** अरे भाई मनुष्य को स्वस्थ्य रखने की हर चीज तुम्हारे अंदर मौजूद है परंतु तुम्हें पैदा करने वाले किसान आत्महत्या कर रहा है और मुझे पीने वाला रोगग्रस्त (नपुंसकता, केंसर, शुगर, बीपी, ब्रेनहेम्रेज आदि बीमारियां) हो रहा है। फिर भी मुझे बनाने वाले करोड़पति बनते है और तुम्हें बनाने वाले रोड़पति, आखिर कारण क्या है?

**जूशः** सत्य कहा तुमने, पढ़े–लिखे और बड़ी–बड़ी डिग्री वाले आज भी मैकाले की मानसिक गुलामी में डूबे हुए है विदेशी कंपनियों के लाल हरे नीले पीले रंग में उन्हें क्वालिटी नजर आती है केमिकल नहीं। *यही बड़ा कारण है ये लोग विज्ञान पढ़ते तो है परंतु वैज्ञानिक बनते नहीं, वरना ठंडा मतलब–टॉयलेट क्लीनर, क्यों पीते उस देश में, जहा अमृत तुल्य अनेकों विकल्प मौजूद है।*

**स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं।**

## निष्क्रिय कर्मचारी ईपीएफ पर ब्याज

देश के निष्क्रिय पड़े ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि योजना) खातों में तकरीबन 43,000 करोड़ रुपये जमा है। श्रम व रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा प्रश्नकाल में कहा है कि सरकार अब निष्क्रिय पड़े ऐसे खातों पर भी ब्याज देगी। निष्क्रिय और लावारिस खातों पर भ्रम की स्थिति को खत्म करने के लिए सरकार ने एक कर्मचारी का एक ईपीएफ एकाउंट कार्यक्रम बनाया है। ईपीएफओ ने पोर्टेबिलटी और पहले के सभी खातों को एक ही खाते में समाहित करने के लिए यूनिवर्सल एकाउंट नंबर जारी किए हैं। 2015–16 में 118.66 लाख दावों का निपटारा ईपीएफओ द्वारा किया गया, 2014–15 में यह आंकड़ा 130.21 लाख और 2013–14 में 123.36 लाख था। 2015–16 में 1.18 लाख दावे निपटान के लिए लंबित बचे हैं।

## सूखे से 6.5 लाख का नुकसान

10 राज्यों में सूखे से अर्थव्यवस्था को 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। सूखे से देश के 256 जिलों के लगभग 33 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। उद्योग संगठन एसोचौम की एक रिपोर्ट में ये बातें कही गईं। उद्योग संगठन एसोचौम ने मानसून पूर्व सीजन के अंतिम सप्ताह के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि औसत से कम बारिश होने से सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, गुजरात और हरियाणा को सूखा घोषित नहीं करने पर राज्य सरकारों को फटकार लगाई।

## नहीं होगा 5,000 से ज्यादा का स्टॉक

चीनी की बढ़ते दामों को काबू में रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा तय कर दी है। इससे अब देश में चीनी के व्यापारी 5,000 क्विंटल से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। अलबत्ता कोलकाता के व्यापारियों को अधिकतम 10,000 क्विंटल चीनी रखने की छूट होगी। सूखे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट आने की आशंका को देखते हुए अधिकांश स्थानों पर चीनी की खुदरा दाम 40 रुपये प्रति किलो के स्तर को पर कर गए हैं। किसी व्यापारी को चीनी की आवक की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने स्टॉक को बेचना होगा। महाराष्ट्र जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में विकराल सूखे की स्थिति को देखते हुए चालू चीनी सीजन 2015–16 के दौरान भारत में चीनी उत्पादन घटकर 2.5 करोड़ टन रह जाने की आशंका जताई जा रही है। पिछले चीनी वर्ष में उत्पादन का आंकड़ा 2.83 करोड़ टन रहा था। देश में चीनी का मार्केटिंग सीजन अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। अभी तक मिलों ने 2.4 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया है। उत्पादन में गिरावट के बावजूद वर्ष की समाप्ति पर चीनी का बकाया स्टॉक 70 लाख टन रहने की उम्मीद है।

## खाते में कम बैलेंस होने पर नहीं होगा जुर्माना

पेनाल्टी के चलते खाते में बैलेंस माइनस में पहुंच जाना अब इतिहास हो गया है। भले ही आपके खाते में पैसे मिनिमम बैलेंस से कम भी हो जाते हैं तो भी आपके ऊपर किसी तरह की पेनाल्टी नहीं पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह नियम पिछले साल से ही प्रभावी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद बहुत से बैंक ऐसे थे जो नॉम मेंटेनेंस चार्ज वसूल कर रहे थे।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर कोई भी बैंक बचत खाते पर चार्ज वसूलता है और इसके चलते बैलेंस जीरो से कम यानी माइनस में जाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत भी कर सकता है। इस तरह के मामले सबसे अधिक सैलरी अकाउंट के साथ देखने को मिले हैं। दरअसल कंपनी किसी भी कर्मचारी का सैलरी अकाउंट खुलवाती है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति नौकरी छोड़कर कहीं और चला जाता है तो वहां पर उसकी कंपनी दूसरा सैलरी अकाउंट खुलवा देती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पुराना बैंक खाता बचत

खाते में बदल जाता है। इसके चलते बैंक अपने ग्राहकों से नॉन मेंटेनेंस चार्ज वसूलने लगते थे, जिसकी वजह से खाते में बैलेंस शून्य से भी कम हो जाता था यानी माइनस में चला जाता था।

## गूगल से 100 करोड़ वसूलने की तैयारी

यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और गूगल जैसे कई इंटरनेशनल संगठन आज भी भारत का गलत नक्शा दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार देश का गलत नक्शा दिखाने पर 100 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 7 साल की सजा का कानून बनाने की तैयारी कर रही है।

## 50 हजार करोड़ का काला धन मिला

अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान 50 हजार करोड़ रुपये की चोरी पकड़ी है। यही नहीं, इसी क्षेत्र में 21 हजार करोड़ रुपये की अघोषित आय का भी पता लगाया गया है। सरकार की कार्रवाई से दो साल में 3,963 करोड़ रुपये के तस्करी के सामान भी जब्त करने में मदद मिली है। यह इससे पिछले दो साल की अवधि की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने वर्ष 2015 के बजट के जरिए काला धन शोधन अधिनियम 2002 में भी संशोधन किया है। संशोधन के उपरांत काला धन शोधन अधिनियम के अंतर्गत अपराध से आय की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है। अब देश के बाहर स्थित संपत्ति, जिसे जब्त करना संभव न हो, के लिए भारत में उसके बराबर मूल्य की संपत्ति की कुर्की को संभव किया जा सके। काला धन शोधन अधिनियम की एक नई धारा, 8, जोडी गई ताकि विशेष न्यायालय के निर्देश पर काला धन शोधन के अपराध में हानि उठाने वाले दावेदार को जब्त संपत्ति फिर से लौटाई जा सके। इसके साथ ही सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 132 में सीमा शुल्क से जुड़ी झूठी घोषणाओं या दस्तावेजों से जुड़े मामलों को अपराध बनाया गया।

## भारत–चीन के विदेशी मुद्रा भंडार लबालब

एशिया की दो आर्थिक महाशक्तियों के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) लबालब दिख रहे हैं। अप्रैल के अंत में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 363 अरब डॉलर के पार चला गया। इसी तरह चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3,219. 7 अरब डॉलर हो गया। अलबत्ता चीन का यह आंकड़ा भारत के मुकाबले लगभग नौ गुना है। फिलहाल एक डॉलर की कीमत 66.50 रुपये के आसपास है, जबकि युआन में यह 6.50 के करीब है।

## ग्रामीण क्षेत्र में भी गैस सिलेंडर की होम डिलवरी

गांवों और दूर–दराज के रसोई गैस (एलपीजी) के ग्राहकों की सहूलियत

के लिए सरकार वहां भी सिलेंडरों की होम डिलीवरी शुरू करने वाली है। इस बारे में योजना लगभग तैयार हो गई है। इस समय देशभर के ग्रामीण इलाकों में करीब 5,000 एलपीजी डीलर तो हैं, लेकिन वे ग्राहकों को घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचाते। इस समय जो नियम है, उसके मुताबिक ग्रामीण इलाके के डीलर की जिम्मेदारी अपने दुकान या गोदाम से सिलेंडर उपलब्ध कराने की है।

पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने वर्ष 2009 में राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना शुरू की थी, जिसके तहत एक ग्रामीण डीलर को अधिकतम 600 ग्राहक बनाने की अनुमति थी। इसी हिसाब से डीलर को महीने में 1,200 रीफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। ग्रामीण डीलरों को महीने में रीफिल सिलेंडर का कोटा बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका टर्नओवर बढ़ सके। इससे पहले एक प्रस्ताव आया था, जिसमें कुछ शुल्क लेकर सिलेंडर की होम डिलीवरी की बात थी, जिसे खारिज कर दिया गया। शहरी एलपीजी डीलरों को 15 किलोमीटर के दायरे में ग्राहक बनाने का अधिकार है। फिर ग्राहक चाहे शहरी क्षेत्र में रहे या ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें होम डिलीवरी देनी पड़ती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के डीलरों पर यह बाध्यता नहीं है।

## गरीबों की उज्ज्वला योजना

गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से निःशुल्क रसोई गैस एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना उनके

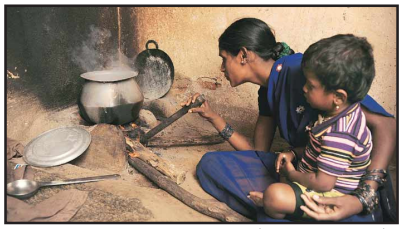

स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊपर उठाने में ऐतिहासिक साबित होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के एकदम गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने का ऐतिहासिक अवसर होगा। जिन परिवारों को लक्ष्य कर यह योजना शुरू की गई है, वह परिवार आज भी गोबर के उपले और लकड़ी जला कर खाना बनाते हैं। ऐसे परिवारों की संख्या करीब 70 करोड़ है, जो आज भी पारंपरिक चूल्हे में उपले और लकड़ी का उपयोग कर खाना बनाने को मजबूर हैं। हालांकि पिछले 60 साल के दौरान इस चूल्हे को उन्नत बनाने के लिए काफी प्रयास हुए हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण, धूम्रपान या घर में खाना बनाने के दौरान लगने वाले धुएं से बच्चों में न्यूमोनिया और बड़ों में फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग, हृदयाघात और फेफरे के कैंसर जैसी बीमारी होती है। इन बीमारियों से जान जाने का काफी खतरा होता है।

## भारत में इंटरनेट की पहुंच अभी भी दूर

केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बाद भी भारत में एक अरब लोगों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं हो पाई है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इसके साथ ही रिटेल

बैंकिंग और फाइनेंस में सख्त रेग्युलेशन के चलते भी इंटरनेट की पहुंच सभी तक नहीं हो पाई है। 10 में से 8 भारतीयों के पास इस वक्त मोबाइल फोन है। लेकिन इसके बावजूद अभी सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिससे वे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएं हैं। भारत अभी विश्व में आईसीटी सर्विसेज का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। अकेले बीपीओ इंडस्ट्री में 31 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें 30 फीसदी महिलाओं की हिस्सेदारी है। भारत में चीन और यूएसए के बाद सबसे अधिक इंटरनेट उपभोक्ता हैं।

## फेसबुक एकाउंट से मिलेगा 1 लाख का लोन

अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप एक लाख रुपए तक के लोन के योग्य है। जी हां अब आप सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जरिए 1 लाख रुपए तक का लोन आसान तरीके से कुछ ही मिनट में हासिल कर सकते हैं। पुणे की एक कंपनी ने अर्ली सैलरी नाम से एक ऐप तैयार किया है। इस एप पर साधारण जानकारी और कुछ मामूली दस्तवेजों को उपलब्ध कराकर आप एक महीने के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का लोन आसानी से बहुत ही कम ब्याज दर पर ले सकते हैं। भारतीय बाजार में यह अपनी तरह की पहली सर्विस है। अमेरिका में इस सर्विस को पेय–डे के नाम से जाना जाता है। एप में लोन लेने के लिए आपकी न्यूनतम सैलरी 20 हजार रुपए महीना होनी जरूरी है। एप पर लोन एप्लाई करते वक्त आपको अपनी सैलरी, लोन अमाउंट और लोन की अवधि का चुनाव करना होगा। आप इस एप की मदद से न्यूनतम 10 हजार रुपए से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। यह कर्ज आपको कम से कम 7 दिन और अधिक से अधि ाक 30 दिन के लिए मिलेगा। अर्ली सैलरी आपको 2.5 फीसदी प्रति माह के इंटरेस्ट रेट पर लोन उपलब्ध कराएगी।

## रिजर्व बैंक ने नोटों में किये महत्वपूर्ण बदलाव

रिजर्व बैंक ने 1000 रुपये के नए नोट जारी किए हैं। इन नोटों में कई सुरक्षात्मक बदलाव किए गए हैं। इन नोटों में दोनों नंबर पैनल में 'R' इनसेट में लिखा होगा। इन नोट में बाकी सभी सुरक्षा फीचर्स को महसूस किया जा सकता है। इनमें आरबीआई गवर्नर के दस्तखत, बड़ा पहचान निशान और लाल लाइन शामिल हैं। नोट के पीछे की तरफ छपने का साल 2016 भी लिखा होगा। नए नोट की डिजाइन पुराने नोटों की तरह ही होगी। वर्तमान में चलन में मौजूद नोट की वैधता को इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। नए नोटों में हुए हैं ये बदलाव नए नोटों में नंबर आरोही क्रम में लिखे होंगे यानि पहला अक्षर सबसे छोटा और उसके बाद के उससे बड़े होते जाएंगे। वहीं पहले तीन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का साइज वहीं रहेगा। 500 रुपये के नोटों में बाएं और दाएं दोनों तरफ ऊपर की ओर पांच छोटी लाल लाइनें होंगी।

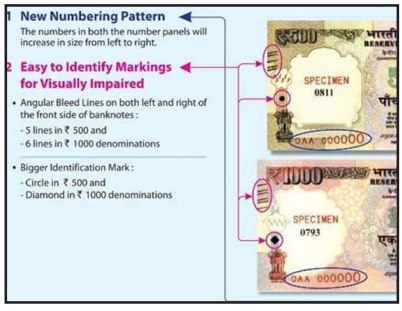

ये 2–1–2 के क्रम में होंगी। 1000 रुपये के नोट में छह लाइनें होंगी। ये 1–2–2–1 के क्रम में होंगी। इन लाइनों को हाथ से छूकर भी महसूस किया जा सकेगा। देखने में अक्षम लोग भी इसे महसूस कर नोट की पहचान कर सकेंगे। वर्तमान में 500 रुपये में मौजूद गोल काला बिंदू और 1000 रुपये में डायमंड का आकार बड़ा होगा। ये दोनों निशान बांयी तरफ नीचे होते हैं।

## 2020 तक 137 अरब की नौकरियां खा जायेगा ड्रोन

वैश्विक बाजार में ड्रोन नौकरियों पर बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा है। एक शोध में दावा किया गया है कि ड्रोन तेजी से इंसानों की जगह ले रहे हैं। ड्रोन का वैश्विक बाजार अभी करीब दो अरब डॉलर का है जो 2020 तक बढ़कर 127 अरब डॉलर का हो जाएगा। गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां ग्राहकों तक सामानों की जल्द डिलीवरी के लिए इनका इस्तेमाल कर रही हैं। छोटे ड्रोन न केवल कुरियर पहुंचा रहे हैं, बल्कि गगनचुंबी इमारतों की खिड़कियां साफ करने, बीमा दावों की जांच और फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव में भी प्रयुक्त हो रहे हैं। परामर्श देने वाली कंपनी पीडब्ल्यूसी के शोध के अनुसार, ड्रोन तकनीक बहुत जल्द ही हमारे रोजमर्रा के जीवन का अंग बन जाएगी।

## टाटा की कर्मचारियों के लिए सुरक्षा घड़ी

टाटा समूह ने कहा कि उसने अपने कारखाने के कर्मचारियों के लिए

विशिष्ट रूप से सेफ्टी वॉच (सुरक्षा घड़ी) विकसित की है जो तत्काल आधार पर सुरक्षा आंकड़े उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने कहा है कि वह भविष्य में प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को पहनने योग्य उपकरण बेचने की तैयारी कर रही है। कारखाने के कर्मचारियों के लिए यह पहला सुरक्षा प्रदान करने वाला धारणा करने योग्य उपकरण है। इस घड़ी को टाटा समूह की कई कंपनियों ने डिजाइन किया है। मूल विचार टाटा स्टील के कर्मचारियों का था, जो जल्द इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे।

## बुलेट ट्रेन का किराया 3300 रू.

रेल मंत्रालय ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए किराया प्रस्तावित किया है। रेलवे की ओर से प्रस्तावित किराया फर्स्ट क्लास एसी किराए का डेढ़ गुना ज्यादा होगा। वर्तमान में दुरंतो एक्सप्रेस में मुंबई से अहमदाबाद का एसी फर्स्ट क्लास का किराया 2200 रु. है। इस लिहाज से बुलेट ट्रेन का किराया 3300 रु. के करीब होगा। जापान में टोक्यो और ओसाका के बीच का किराया 8500 रु. है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 550 किमी. है। वहीं मुंबई–अहमदाबाद के बीच 508 किमी का फासला है। भारत में बुलेट ट्रेन के पहले चरण में 350 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार होगी। इस पर 320 किमी/घंटे की रफ्तार से ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

## भारतीयों की औसत संपत्ति में 400% इजाफा

वर्ष 2005 से 2015 के दस साल में भारतीयों की औसत संपत्ति 400 प्रतिशत बढ़ी जबकि इसी अवधि में यूरोपीय नागरिक की औसत संपत्ति में पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक ताजा रपट में यह निष्कर्ष निकाला गया है।

रपट के अनुसार इस दौरान भारत, चीन व वियतनाम जैसे उदीयमान बाजारों में औसत संपत्ति 400 प्रतिशत बढ़ी। औसत यूरोपीय नागरिक की मौजूदा औसत संपत्ति लगभग 86,000 डॉलर है। बीते दस साल में इसमें पांच प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं अन्य विकसित देशों से तुलना की जाए तो आलोच्य अवधि में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति की औसत संपत्ति 100 प्रतिशत से अधिक, जबकि कनाडा में 50 प्रतिशत बढ़ी।

रपट के अनुसार यूरोप में प्रति व्यक्ति औसत संपत्ति में आई गिरावट की मुख्य वजह संपन्न लोगों का अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों को चले जाना है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में भी यूरोप से प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार एशिया विशेषक चीन, भारत, श्रीलंका, फिलीपीन व वियतनाम को जाते रहेंगे। ❑❑

# सौर ऊर्जा: भारत का भविष्य

**स्वदेशी जागरण मंच** देश भर में ''सौर उर्जाः भारत का भविष्य'' विष पर सेमिनार/संगोष्ठियां के माध्यम से जन–जागरण अभियान चला रहा है। इस अभियान को गति देने के लिए मंच द्वारा केंद्रीय स्तर पर ''भारत सौर–उर्जा डवेलपमेंट फोरम'' (बी.एस.डी.एफ.) का गठन किया है। इस फोरम के राष्ट्रीय संयोजक पेसीफिक यूनिवर्सिटी (राजस्थान) के उप–कुलपति एवं स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा है। इनका सहयोग स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं राजस्थान के संगठक श्री सतीश कुमार कर रहे है। इसके अतिरिक्त सौर–उर्जा क्षेत्र में काम करने वाले 20–22 उद्योगपतियों एवं वैज्ञानिकों का समूह भी फोरम में कार्यरत है। इसी जन–जागरण अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रांत में भी सभी पांच विभागों में एक–एक कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम 22 अप्रैल 2016 को देवसदन (कुल्लू) में संपन्न हुआ। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता श्री सतीश कुमार, श्री सतीश चावला (उत्तर क्षेत्रीय विचार मंडल प्रमुख), श्री नरोत्तम ठाकुर (प्रांत संयोजक), हिम उर्जा के परियोजना अधिकारी नारायण दत्त, जिला संघ चालक श्री राजीव करीर, स्वदेशी जागरण मंच के श्री गौतमराम, श्री हरीश तथा कुल्लू इकाई के कार्यकर्ताओं सहित कुल 350 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री सतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2022 तक अपने देश में 100 गीगावाट सौर उर्जा का उत्पादन होना है, इसमें से 40 गीगावाट बिजली का उत्पादन घर की छतों पर होगा और नेट मेटरिंग तकनीक द्वारा सरकारी ग्रिड तक पहुंचेगी और सरकार इसे खरीदेगी। उन्होंने कहा कि 70,000 तक की लागत में एक किलोवाट तक बिजली का उत्पादन हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में 70 प्रतिशत सब्सिडी के साथ यह लागत 25000 प्रति किलोवाट तक आयेगी। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा उत्पादन से पर्यावरण सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा देश की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। साथ ही सबसे सौर उर्जा का उत्पादन करने का आग्रह किया तथा समाज में भी इस जन–जागरण अभियान को गति देने पर बल दिया। ❑

## जोधपुर बैठक

सनसिटी को सोलर सिटी बनाने के उद्देश्य को लेकर स्वदेशी जागरण मंच एवं भारत सोलर डवलपमेंन्ट फोरम की जोधपुर स्थित स्टील रिरोलर्स एसोशियशन भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गुजरात के उद्योगपति व यूरो सोलर सैल के निर्माता श्री राजाबाबू, सी.ए. योगेश बिड़ला, श्री धर्मेंद्र दुबे (राजस्थान प्रांत संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच), श्री राधेश्याम बंसल, श्री अतुल भंसाली, श्री अनिल वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किये। जोधपुर के प्रमुख सौर ऊर्जा उद्यमी अंकुर सेठिया, विपुल बाफना, जयन्त जांगिड़, राजदीप गौड़, नीरज यादव, दिनेश चौपड़ा, जय वर्मा, मंच के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य देवेन्द्र डागा, महेश जांगिड़, अनिल माहेश्वरी, विनोद मेहरा, मिथिलेश कुमार, रोहिताश पटेल, सत्येन्द्र प्रजापति, अशोक गुप्ता, छोटू सिंह ईन्दा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।❑

## दिल्ली बैठक

स्वदेशी जागरण मंच, झंडेवालान विभाग द्वारा दिनांक 8 मई 2016 को प्रातः 10.30 बजे 'सौर उर्जा–स्थायी विकल्प' विषय पर गोष्ठी का आयोजन 26, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, ए.बी.वी.पी. कार्यालय, आईटीओ, नई दिल्ली पर किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर भारत संगठक एवं अखिल भारतीय सह विचार मंडल प्रमुख श्री सतीश कुमार एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता डा. ममता त्यागी ने की। सम्मानीय अतिथि के रुप में चौधरी ओम प्रकाश (पूर्व अध्यक्ष आर्य समाज), स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत के सह संयोजक श्री रविन्द्र सोलंकी एवं प्रांत प्रचार प्रमुख श्री यसवन्त सिंह सहित अन्य बुद्धिजीवी स्वदेशी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ❑